छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 76 ■ अम्बिकापुर, बुधवार 18 मार्च 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर और सीलमुद्रा का उपयोग कर शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव पारित

बैठक में सचिव कहा-दबाव डालकर बाहरी व्यक्ति ने प्रस्ताव में कराया हस्ताक्षर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत झिरमिटी में सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर करके और सील मोहर लगाकर अंग्रेजी शराब दुकान खोलने के लिए प्रस्ताव पास करने का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचे ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचों और ग्रामीणों ने इसकी जानकारी कलेक्टर के जनर्दशन में देकर कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने कहा है कि फर्जी ग्रामसभा और पारित प्रस्ताव के आधार पर अगर शराब दुकान खोला जाता है, तो वे आन्दोलन की राह पर अग्रसर होंगे। इधर मामले में पंचायत सचिव ने दबाव डालकर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव में हस्ताक्षर लेना स्वीकार किया है।

ग्राम पंचायत झिरमिटी के सरपंच चंदन एक्का व पंचों ने बताया कि 13 मार्च 2025 को पंचायत क्षेत्र के अलकापुरी में अंग्रेजी शराब दुकान खोलने संबंधी पारित किए गए प्रस्ताव का उस समय पर्दाफास हुआ, जब कुछ दिन पहले आबकारी विभाग की टीम शराब दुकान

खोलने के लिए गांव में जगह तलाशने के लिए पहुंची थी, लेकिन ग्राम के निर्वाचित सरपंच और पंच इससे बेखबर थे। आबकारी विभाग के टीम की ग्राम अलकापुरी में पहुंचने की जानकारी मिलने पर सरपंच, पंच सहित अन्य ग्रामीण भौचक रह गए। इसे गंभीरता से लेते हुए सरपंच ने अपने अन्य सहयोगियों और ग्रामीणों के साथ वास्तविकता से रूबरू होने का प्रयास किया तो सामने आया कि शराब दुकान खोलने के लिए हाईवे से निर्धारित दूरी के मापदंडों को पूरा करते हुए स्थल निर्धारित करने के लिए टेंडर भी हो चुका है और 6 लोगों ने इसके लिए 25-25 हजार रुपये दिया है। आबकारी विभाग की टीम नए सत्र से शराब दुकान संचालन करने के लिए जगह तलाशने ग्राम अलकापुरी पहुंची। सरपंच का कहना है कि फर्जी प्रस्ताव को उन्होंने देखा तो उसमें ग्राम पंचायत के सरपंच का सील मोहर लगा था। सरपंच द्वारा हिन्दी में किया जाने वाला हस्ताक्षर अंग्रेजी में था। इसके बाद फर्जी ग्रामसभा का प्रपत्र तैयार करके किसने शराब दुकान के लिए प्रस्ताव तैयार किया, खोजबीन शुरू हुई, लेकिन फर्जीवाड़ा में शामिल चेहरा सामने नहीं आ पाया है। फर्जी प्रस्ताव में ग्राम सभा अध्यक्ष धनेश्वर टेकाम सहित अन्य सदस्यों के नाम का उल्लेख है, इन्हें भी तत्संबंध में कोई जानकारी नहीं है, और न ही वे ग्रामसभा में उपस्थित ही थे।

13 मार्च 2025 को फर्जी ग्रामसभा में पारित हुआ प्रस्ताव

ग्राम पंचायत झिरमिटी में शराब दुकान के लिए फर्जी प्रस्ताव पास करने का मामला संज्ञान में आने पर 15 मार्च को सरपंच चंदन एक्का की अध्यक्षता में अति आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में ग्रामीणों के संज्ञान में लाया गया कि ग्राम पंचायत झिरमिटी में शासन के द्वारा अंग्रेजी शराब दुकान खोला जा रहा है। फर्जी ग्रामसभा 13 मार्च 2025 को करके सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर से प्रस्ताव पास करने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने विरोध जाहिर किया। सरपंच ने जब पंचायत के सचिव से इस संबंध में पूछा तो वह बताया कि किसी बाहरी व्यक्ति ने दबाव डालकर प्रस्ताव बनवाया, जिसमें उनका हस्ताक्षर है, मगर हेंडराइटिंग नहीं है। सरपंच के हस्ताक्षर के संबंध में पूछने पर सचिव ने कहा कि उक्त व्यक्ति ही अंग्रेजी में हस्ताक्षर किया होगा। पंचों ने भी फर्जीवाड़ा करके अंग्रेजी शराब दुकान खोलने की जा रही कवायद पर आपत्ति जताते हुए इसे निरस्त करने पर जोर दिया है।

शराब भट्ठी खोलकर गांव के लोगों को बर्बाद नहीं होने देंगे

कलेक्टर से मुलाकात करके फर्जीवाड़ा की जानकारी देने सरपंच के साथ पहुंचे उपसरपंच गायत्री दास महंत, भूतपूर्व उपसरपंच चित्रांगत पुरी गोस्वामी, पंच छत्रपाल टेकाम, गणेश राम राजवाड़े, रामलगन मराबी, वनस्पति एक्का, छन्दनी एक्का, चम्पा राजवाड़े, फुलेश्वरी, गांव की ही किरण एक्का सहित अन्य ने कहा कि वे शराब दुकान खुलवाकर अपने गांव को बर्बादी की राह पर अग्रसर नहीं होने देंगे। पूर्व से ही वे गांव में अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने के पक्षधर नहीं रहे, यहां तो शराब भट्ठी खोलने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी पढ़ाई-लिखाई की जगह नशे के गर्त में जाए। अगर शासन-प्रशासन फर्जी प्रस्ताव के आधार पर मनमानी पर उतारू हुआ, तो वे आन्दोलन की राह पर अग्रसर होंगे। इनके द्वारा फर्जी प्रस्ताव के जांच और आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की भी मांग की गई है।

ग्राम पंचायत की ओर से शराब दुकान खोलने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर हैं। इसी आधार पर शासन से शराब दुकान खोलने के लिए अनुमति मिली है। शराब दुकान

खोलने की प्रक्रिया एक साल से चल रही है, टेंडर हो चुका है। टेंडर जब समाचार पत्रों में जारी हुआ तो कोई विरोध नहीं हुआ। अवैध शराब का धंधा करने वाले कतिपय लोग नहीं चाहते कि शासकीय शराब की दुकान खुले। हमारा काम शासन को पहुंचने वाली राजस्व क्षति को रोकना है।बात प्रस्ताव सही नहीं होने की सामने आई है, इसका परीक्षण कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एल.के. गायकवाड़
जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा

पहाड़ी कोरवा समाज की बैठक में गूंजा फर्जी पट्टा निरस्त करने का मुद्दा

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के विनायकपुर में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आश्रम पारा में पहाड़ी कोरवा जनजाति समाज की भव्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर रहे, वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग शामिल हुए। बैठक दौरान समाज में चल रही गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए आरोप लगाया कि गांव की पुश्तैनी जमीन का कुछ बाहरी लोगों द्वारा फर्जी तरीके से पट्टा बनवा लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पूर्वजों की जमीन पर एक ही भूमि के लिए एक साथ 14 लोगों के नाम पट्टा जारी कर दिया गया, जो गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। ग्राम पौड़ी खुर्द रजुवाढोढी में पहाड़ी कोरवा परिवार पिछले 60-65 वर्षों से खेती-किसानी करते आ रहे थे। उनके पूर्वजों ने जंगल और झाड़ियों से भरी जमीन को साफ करके उसे खेती योग्य बनाया था और वर्षों तक वहां अरहर सहित अन्य फसलें उगाते रहे। आरोप है कि वर्ष 1971-72 के बंदोबस्त के दौरान कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त भूमि का अवैध पट्टा बाहरी लोगों के नाम पर बना दिया गया। इतना ही नहीं, भू माफियाओं ने अपने परिवार के कई सदस्यों के नाम पर भी पट्टा बनवा लिया और मूल कब्जाधारियों को जमीन खाली करने की धमकी दी। पीड़ितों ने बताया कि इस मामले की शिकायत तहसीलदार से लेकर राष्ट्रपति तक की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पट्टा बनाते समय न तो इश्तहार प्रकाशित किया गया और न ही मौके की जांच की गई। बैठक में ग्रामीणों ने अपनी समस्या समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर के समक्ष रखते हुए सामाजिक हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि पुश्तैनी जमीन पर हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके और न्याय मिल सके।

जंगलों की हो रही है अंधाधुंध कटाई जिम्मेदार मौन

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई लगातार जारी है, लेकिन जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों को काटकर वहां टमाटर सहित अन्य फसलों की खेती की जा रही है और कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की मंशा से इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं।

वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में 16 मार्च से प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला केन्द्रीकृत वार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26 प्रारंभ हो चुका है, जो क्रमशः समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक तथा 9 बजे से 12 बजे तक संचालित होंगे। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के केन्द्रीकृत वार्षिक परीक्षाओं के दौरान 16 मार्च से 8 अप्रैल तक शाला संचालन समय में परिवर्तन कर विद्यालयों का संचालन प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक नियत किया गया है। हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा, स्थानीय परीक्षा एवं मूल्याकन कार्य इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

आपसी विवाद के बाद युवक की जान लेने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार

शव फेंकने में डेढ़साला किया सहयोग, माता-पिता ने घटनास्थल को गोबर से लीपा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। उदयपुर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद होने पर आरोपी ने डंडा एवं टांगी के बेट से वार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद आरोपी द्वारा अपने डेढ़साला के साथ मिलकर शव को डबरी में फेंक दिया था। वहीं आरोपी के माता-पिता ने घर में गिरे खून को साफ करके गोबर से लिपाई कर साक्ष्य को विलोपित करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा, टांगी, मोटरसायकल, मोबाइल फोन सहित अन्य साक्ष्य बरामद किया है।

जानकारी के मुताबिक मनोज कुमार निवासी हनुमानगढ़ द्वारा थाना उदयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 15 मार्च को उसका छोटा भाई शीतल अपने साथी टेकराम के साथ मोटरसायकल से शाम करीब 04 बजे ग्राम हनुमानगढ़ से पोतका निवासी दिनेश कुमार के घर में शादी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। 16 मार्च को उसे मोबाइल फोन में सूचना मिला कि उसके छोटे भाई शीतल कुमार को ग्राम पोतका में प्रमोद अपने ही घर में मारपीट करके गांव के पुलिया के पास डबरी के पानी में फेंक दिया है। जब वह मौके पर गया तो शीतल के सिर में गंभीर चोंट का निशान नजर आ रहा था और उसका शव डबरी के पानी में पड़ा हुआ था। डबरी के बगल में जूट का खून लगा हुआ बोरा, मोबाइल और गमछा पड़ा था। मृतक के भाई ने प्रमोद के द्वारा ही शीतल के साथ मारपीट करने और हत्या करके शव को डबरी में फेंक देना बताया गया था, जिस पर पुलिस थाना उदयपुर में धारा 103(1), 238(ए), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण करके डबरी के बगल से खून से लगा जूट का बोरा, मोबाइल फोन एवं गमछा जब्त करके मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक सिर में चोट लगने से होने एवं हत्यात्मक प्रवृत्ति का लेख किया था। आरोपी प्रमोद सिंह पिता बहादुर 20 वर्ष निवासी ग्राम पोतका ने पूछताछ में शीतल कुमार से आपसी विवाद होने पर डण्डा एवं टांगी के पासा से सिर में वार करके हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद वह शव को अपने डेढ़साला राजेश कुमार पिता शिवप्रसाद उर्फ गोपी 20 वर्ष निवासी ग्राम केवरा बैगापारा, थाना लखनपुर के साथ मिलकर डबरी में फेंक दिया था। आरोपी प्रमोद सिंह के पिता बहादुर पिता तेजु राम 42 वर्ष न मां पवारों 40 वर्ष ने घटना के बाद घर में गिरे खून को साफ करके गोबर से लिपाई कर दिया था। प्रकरण में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, प्रधान आरक्षक संजय नागेश, राजेश चतुर्वेदी, आरक्षक रविन्द्र साहू, सूरजबली, देवेंद्र सिंह सक्रिय रहे।

संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कब्जे और वन अमले के संलिप्तता की हो जांच

पार्षद ने मुख्यमंत्री, वन मंत्री को लिखा पत्र, कहा-प्लांटेशन का हुआ सफाया

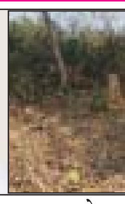

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर से लगे संरक्षित वन क्षेत्र खैरबार बधियाचुंवा, बाकी डेम के कक्ष क्रमांक 2581 एवं 2582 में बेतहाशा अवैध कब्जे पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच कराने बावत वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पार्षद आलोक दुबे ने पत्र प्रेषित करके छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, वन मंत्री का ध्यानाकर्षण कराया है। इसमें उल्लेख है कि शहर की सीमा से लगा सघन एवं संरक्षित वन क्षेत्र करीब 1500 एकड़ के आस-पास का है। इसमें महामाया पहाड़, खैरबार, बधियाचुंवा बाकी डेम एवं लालमाटी लुचकी का इलाका आता है। जनवरी 2025 एवं जून 2025 में महामाया पहाड़ एवं रनपुर खुर्द चोरकाकछार में जिला प्रशासन एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने शासन के निर्देश पर करीब 100 मकानों के अतिक्रमण को हटाया, इसके बाद भी इस हरे-भरे वन संरक्षित क्षेत्र में अवैध कब्जा की प्रकिया नहीं रुक रही है। आरोप है कि वन विभाग के बीटगार्ड, वन रक्षक, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर, रेंजर, एसडीओ वन की भू-माफियाओं से मिलीभगत एवं लाखों रुपये की अवैध वसूली के कारण इस संरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे की खबर लेने ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर वन संरक्षित क्षेत्र में रेंजर, एसडीओ एवं वन मण्डलाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते है। उन्होंने मुख्यमंत्री, वन मंत्री सहित वन विभाग के उच्च अधिकारियों से आग्रह किया है कि अति महत्वपूर्ण वन संरक्षित क्षेत्र, जो संपूर्ण अंबिकापुर का ऑक्सीजन हब है, इस इलाके में वन विभाग के उच्चधिकारियों को टीम का गठन करने के लिए निर्देशित किया जाए और अवैध अतिक्रमण को हटाकर अगामी बारिश में नए सिरे से पौधा रोपध कराकर हरियाली वापस लाने की पहल की जाए। उन्होंने कहा है कि अभी से कार्य जोजना बनाकर जांच टीम को मौके का निरीक्षण करना होगा और इस मामले में वन विभाग का अमला, जो लाखों रुपये अवैध उगाही करके कब्जा को संरक्षण देने में लगा है, उनके उपर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि होली के आस-पास खैरबार क्षेत्र में सागौन प्लांटेशन को बड़ी मात्रा में काटकर अवैध अतिक्रमण का प्रयास किया गया है।

झिलमिली स्टेट के छोटे राजा की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन

छ.ग.फ्रंटलाइन भैयाथान। झिलमिली स्टेट के छोटे राजा की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वजनों ने वार्षिक श्राद्ध पूजन कर ब्राह्मण भोज और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया।

छोटे राजा के नाम से विख्यात विन्ध्येश्वरी प्रताप सिंह के प्रथम पुण्य तिथि पर इंद्रप्रस्थ भैयागढ़ी में उन्हें आम लोगों एवं स्वजन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें याद करते हुए रामेश्वर प्रताप सिंह ने कहा कि लोगों के सहयोग के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे, साथ ही गांव में आपसी झगड़ा-विवाद को निर्विवाद रूप से सुलझाने में माहिर थे। यही कारण था कि उन दिनों थाना में कम मामला जाया करता था, यही विश्वास उन्हें ग्रामीणों से जोड़ता था। खेल के प्रति उनका लगाव असीम था, वे फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। जिला पंचायत सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि परिवार को एक सूत्र में उन्होंने बांधकर रखा, आज भी पूरा परिवार एकजुट है। वे पूरे नवरात्र में कुदरगढ़ में पूजा-अर्चना करते थे, जिसे परिवार आज भी

निभा रहा है। आसपास के क्षेत्र में रामायण प्रतियोगिता में वे निर्णायक की भूमिका बखूबी निभाते थे। हमारा परिवार उनके बताए पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में ललित सिंह, अमरेश्वर प्रताप सिंह, शिवम सिंह, योगेश प्रताप सिंह, ललित सिंह, अजय प्रताप सिंह, आशीष सिंह सहित परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे।

सैंपल में निकला असली सोना, बाद में नकली सोना थमाकर ऐंठे 2.20 लाख

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के चांदनी थाना अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा नकली सोना थमाकर दो लाख 20 हजार रुपये की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है।

भैयाथान थाना क्षेत्र के ग्राम दर्रीपारा निवासी बालरूप गुप्ता पिता सुखई 45 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि होली पर्व के 4-5 दिन पहले ग्राम पपराखांड के सोनू ने उसे बताया कि उसके मोबाइल में फोन करके एक व्यक्ति ने सोना खरीदने के लिए ऑफर दिया था, जिस पर वह सोना खरीदने के लिए हामी भर दिया था। इसके बाद 06 मार्च को सोनू के साथ सोना का सेम्पल देखने बिहारपुर नवाटोला गए थे। यहां 02 व्यक्ति मिले, जो सोना दिखाए और उसी में से थोड़ा सोना कट करके सैम्पल दिए थे। सोना का सैंपल ले जाकर जब वे भैयाथान में सोनार के पास चेक कराए तो सोना असली था। इसके बाद सोना खरीदने के लिए उन्होंने सौदा किया और 11.03.2026 को मैं 2 लाख 20 हजार रुपये लेकर गांव के केवरा निवासी जयप्रकाश के साथ रेडीपहरी ठाड़पाथर थाना चांदनी चैक में पहुंचे, यहां वही दोनों व्यक्ति मिले, जो सोने का बिस्किट कपड़े में लपेट कर दिए और 2 20 बीस हजार रुपये लेकर दोनों चले गए। इसके बाद दिए गए सोना को भैयाथान में सोनार दुकान में ले जाकर चेक कराए तो सोना नकली निकला। रिपोर्ट पर पुलिस अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

मैदानी भ्रमण और आवास चौपाल के माध्यम से पीएम आवास में लाएं प्रगति : कलेक्टर

मनरेगा कार्यों को प्राथमिकता से 31 मार्च तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला पंचायत अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आवास योजना की जनपदवार गहन समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों, निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने अधूरे आवासों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लापरवाही बरतने एवं संलिप्तता पाए जाने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे नियमित रूप से मैदानी भ्रमण कर आवास निर्माण कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवास चौपाल एवं जन चौपाल के माध्यम से आवासों की सतत समीक्षा करें तथा हितग्राहियों से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें शीघ्र आवास पूर्ण करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शासन की

महत्वाकांक्षी योजना का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों को मिल सके। इस दौरान पीएम जनमन आवासों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि शीघ्र लक्ष्य पूर्ण कर अपेक्षित प्रगति लाएं। बैठक में कलेक्टर ने मनरेगा अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों और विगत पूर्ण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी एवं अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों को 31 मार्च 2026 तक निर्धारित समय-सीमा में प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने महिला समूहों को उद्यमिता से जोड़ने और उनके आय में बढ़ोत्तरी करने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत लखपति दीदी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों में शत-प्रतिशत परिवारों का समावेशन कर अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ना है, ताकि महिलाओं की आजीविका में सतत वृद्धि हो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे स्वच्छता कार्यों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि सभी गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यों में गति लाए। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सर्व जनपद सीईओ, सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा, कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, बीसी प्रधानमंत्री आवास, तकनीकी सहायक उपस्थित थे।

कोटबहरा में फसलों व बोर को हाथियों ने पहुंचाया नुकसान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत कल्याणपुर के कोटबहरा गांव में सोमवार की शाम पहुंचे पांच सदस्यीय हाथियों के दल ने रात में दो ग्रामीणों के बोर को क्षतिग्रस्त करने के अलावा फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के रिहायशी इलाके के पास डटे रहने से स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है।ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की शाम पांच सदस्यीय हाथियों का दल बलरामपुर जिला के सरहद से ग्राम पंचायत कल्याणपुर के कोटबहरा गांव में पहुंचे थे। हाथियों के दल ने रात कोटबहरा निवासी ईश्वर सिंह व जीतू राम के बोर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके गेहूं, गन्ना, गर्मी सीजन के धान फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का दल मंगलवार की शाम तक कोटबहरा के जंगल में ही डटे हुए हैं और रात होने पर पुनः रिहायशी इलाके की ओर रुख कर दिए। हाथियों के क्षेत्र में विचरण करने से स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है और ग्रामीण रात भर रतजगा करने मजबूर हैं। हाथियों के क्षेत्र में विचरण करने पर वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ डटी हुई है और लोगों को समझाइश देते हुए हाथियों को जंगल की ओर वापस लौटाने का प्रयास कर रही है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय से इन इलाकों में हाथियों की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं, जिसके कारण सीमावर्ती गांवों के लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। कोटबहरा के आसपास घने जंगल और खेत होने के कारण हाथियों का दल अक्सर भोजन की तलाश में गांवों की ओर रुख कर लेता है। यही वजह है कि ग्रामीणों में हर बार हाथियों के आने की खबर से भय और चिंता का माहौल बन जाता है। कुछ महीने पहले भी हाथियों का दल इस इलाके में पहुंचा था। उस समय हाथियों ने गांव में जमकर उत्पात मचाते हुए करीब एक दर्जन मकानों को क्षतिग्रस्त कर खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया था।

गठित की गई टीम

पांच सदस्यीय हाथियों के दल के कल्याणपुर कोटबहरा क्षेत्र में पहुंचने पर डीएफओ के निर्देश पर हाथियों को खदेड़ने व निगरानी हेतु टीम का गठन किया गया है। जिसमें वन विभाग के देव कुमार के अलावा अखिलेश प्रधान, यशवंत सिंह, दुष्यंत सिंह, मोहन सिंह को शामिल किया गया है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भुनेश्वर सिंह भी सक्रिय हैं।

कागजों तक सिमटा हाई मास्ट

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों जब हाथियों द्वारा जमकर नुकसान पहुंचाया गया था, तब महिला बाल विकास मंत्री व भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी यहां पर प्रभावित गांव का दौरा की थीं। उन्होंने यहां पर ग्रामीणों के मांग पर हाई मास्ट लगवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक लोगों की मांग केवल कागजी कोरमपूर्ति तक ही सिमट कर रह गई है। जिससे स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है।

यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से श्रमिक नेता से ठगी मामले में अपराध दर्ज

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के श्रमिक नेता के साथ सप्ताह भर पूर्व यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से करीब 193993 रुपए की हुई ठगी मामले में आज पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल आवासीय 1 सी कॉलोनी क्वार्टर नंबर 42 निवासी महेश कुमार गुप्ता पिता स्व. दयाचंद गुप्ता जो एसईसीएल में कार्यरत हैं, के भारतीय स्टेट बैंक खाते से सप्ताह भर पूर्व दो दिनों में कई किश्तों में रकम निकाल ली गई थी। पीड़ित को इस बात की भनक तक नहीं लगी और ठग बड़ी चालाकी से अपना काम कर गए। घटना 10 मार्च की रात करीब 11.56 बजे एक अनजान नंबर से आए मिस्ड कॉल से हुई। जब महेश गुप्ता ने उस नंबर पर वापस कॉल किया, तो उनका नंबर बंद बताया गया। घबराए पीड़ित ने तत्काल जियो हेल्पलाइन नंबर 199 पर संपर्क किया, जहां उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली कि उनके ही नंबर को गुम बताकर बंद करा दिया गया है। हालांकि आधार कार्ड के अंतिम चार अंक बताने के बाद उनका नंबर दोबारा चालू कर दिया गया। लेकिन यहीं से ठगों की असली चाल शुरू हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि घटना दिवस रात करीब 12.50 बजे एक अन्य नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को मुंबई स्थित एसबीआई कंफर्मेशन डिपार्टमेंट का अधिकारी बताया। उसने कहा कि खाते से संदिग्ध यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं और सुरक्षा के लिहाज से यूपीआई होल्ड कर दिया गया है। इतना ही नहीं ठगों ने भरोसा जीतने के लिए पीड़ित के खाते का एक महीने का स्टेटमेंट भी ईमेल कर दिया। जब महेश गुप्ता ने स्टेटमेंट देखा, तो उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि ठगों ने 9 मार्च को 7 बार में 94997 रुपए व 10 मार्च को 6 बार में 98 996 रुपए अलग-अलग अज्ञात खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। खास बात यह है कि ये सभी ट्रांजेक्शन पीड़ित की जानकारी के बिना हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने थाना बिश्रामपुर में लिखित आवेदन दिया था और साथ ही एनसीआरबी पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मंगलवार को मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) एवं 66 डी के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध मोबाइल नंबरों व बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है।

कोल परिवहन पर लगी रोक के बाद हुई बैठक में 31 तक आवागमन पर बनी सहमति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। अमेरा खदान तक जाने वाले मार्ग को लेकर पिछले दिनों पिपरखांड के पास ग्रामीणों द्वारा कोल परिवहन रोक दिए जाने से क्षेत्र में हलचल मच गई थी। सड़क की जर्जर हालत, धूल और दुर्घटनाओं की आशंका को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया था, जिससे कोयला परिवहन पूरी तरह ठप हो गया था, लेकिन घंटों बाद प्रशासन के हस्तक्षेप उपरांत कोयला परिवहन कार्य शुरू करा दिया गया था। इसी तारतम्य में मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को लखनपुर नायब तहसीलदार सर्वेश पटेल की उपस्थिति में खदान प्रबंधन की ओर से जीएम ऑपरेशन जीके राय, अमेरा सब एरिया मैनेजर ओपी अटल, मैनेजर समय लाल धैर्य, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी अमरेंद्र नारायण, एसओ सिविल रविन्द्र खलखो और पंचायत जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के बीच अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद आखिरकार एक सहमति बनी, जिससे प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। बैठक में यह

निर्णय लिया गया कि 31 मार्च तक कोल परिवहन और आम आवागमन बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रशासन और प्रबंधन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इसके बाद सड़क निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा और उसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग केवल बेहतर सड़क और सुरक्षित आवागमन की है। धूल के गुबार और खराब सड़क के कारण उन्हें रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खदान प्रबंधन ने भी भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। प्रशासन की इस पहल से फिलहाल टकराव की स्थिति टल गई है। ज्ञात हो कि अमेरा खदान प्रभावित क्षेत्र पिपरखांड गांव के लोगों ने बदहाल सड़क व अन्य अव्यवस्था से नाराज होकर गत दिनों 13 मार्च को सड़क जाम करके कोल परिवहन कार्य को घंटों बंद करा दिया था।

पदीय गरिमा के विपरीत कार्य करने पर प्रधानपाठक निलंबित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गैना वाड्रफनगर के प्रधानपाठक आर.एन.कोल के द्वारा विद्यालय के उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर संस्था से चले जाने एवं संस्था से जाने के बाद गांव/घरों में शराब का सेवन कर घुमने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना प्रथम दृष्टया सही पाया गया। कोल के द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती गई।

उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3, नियम-7, नियम-23 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा संभाग के द्वारा प्रधानपाठक आर.एन. कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक कोल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

गांजा तस्करी मामले में फरार दो और युवक 11 दिन बाद गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में लटोरी पुलिस ने एक ऐसे गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो ओडिशा से मादक पदार्थ लाकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में खपाने की फिराक में था। इस पूरे मामले में जहां पहले तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए थे, वहीं पुलिस को चकमा देकर फरार हुए दो आरोपी भी आखिरकार 11 दिन बाद पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। लटोरी पुलिस ने बताया कि गत दिनों 6 मार्च को जब लटोरी पुलिस टीम अंबिकापुरङ्कबनारस हाईवे पर स्थित देशी ढाबे के सामने वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी अंबिकापुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक सफारी वाहन क्रमांक सीजी 15 ईजी 4455 को रोककर तलाशी ली गई। जैसे ही पुलिस को वाहन में संदिग्ध सामान होने का अंदेशा हुआ, उसी दौरान उसमें सवार दो युवक अचानक दरवाजा खोलकर कूद पड़े और खेतों की ओर भाग निकले।

पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन दो युवक फायदा उठाकर फरार हो गए। वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को दो झोलों में छिपाकर रखे गए 8 पैकेटों में कुल 8.990 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन में सवार जीवधन पैकरा, सुरेंद्र कुमार लास्कर और ललित यादव को गिरफ्तार कर तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फरार आरोपियों क्रमशः महेश कुमार यादव और परमेश्वर देवांगन की तलाश के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। आरोपी इतने शातिर थे कि अपने मोबाइल फोन बंद कर बार-बार ठिकाना बदलते रहे, जिससे पुलिस को लगातार चकमा मिलता रहा। गांव और आसपास के क्षेत्रों में उनकी गतिविधियों को लेकर पुलिस ने गुप्त निगरानी भी शुरू कर दी थी। करीब 11 दिनों की तलाश के बाद मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी अपने-अपने घर लौट आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम दो अलग-अलग स्थानों पर घेराबंदी कर कार्रवाई की और दोनों आरोपी महेश कुमार यादव पिता रामरतन यादव 30 वर्ष निवासी बरौधी भटगांव व परमेश्वर देवांगन पिता रामधारी 24 वर्ष निवासी सोनगरा पीपरपारा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वे पहले से गिरफ्तार साथियों के साथ मिलकर ओडिशा के सोनपुर क्षेत्र से एक स्थानीय सप्लायर से गांजा खरीदते थे और उसे छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में बेचने के लिए लाते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस अब इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के अन्य सदस्यों और सप्लायर तक पहुंचने के प्रयास में जुट गई है। इस पूरी कार्रवाई में लटोरी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आरक्षक विकास कुमार मिश्रा और संतोष जायसवाल सक्रिय रहे।

अजबनगर में वारूनी महामेला कलश यात्रा के साथ हुआ शुरू

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत अजबनगर क्षेत्र इन दिनों भक्ति और उत्साह के रंग में पूरी तरह रंग गया है। श्री हरिचांद ठाकुर के 215 वें जन्म महोत्सव के अवसर पर आयोजित वारूनी महामेला का शुभारंभ सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन श्री किरण चांद हरि भजन आश्रम अजबनगर में किया जा रहा है, जहां दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचकर इस धार्मिक महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पहले दिन सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर नगर भ्रमण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे मार्ग को भक्ति और आस्था से सराबोर कर दिया।

महोत्सव के दूसरे दिन 17 मार्च को गंगा स्नान एवं निसान दल के आगमन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की विधिवत शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही पूजा-अर्चना कर अपने जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।

आयोजन समिति के संदीप सरकार ने बताया कि 18 मार्च को जेएमडी म्यूजिक ग्रुप मध्य प्रदेश द्वारा जीवंत झांकी के साथ भजन संध्या का विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्ति संगीत की मधुर धुनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होंगे। वहीं 19 मार्च को रंगारंग धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ बाहर से आए कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव का समापन 20 मार्च को धार्मिक प्रवचन एवं शांति सभा के साथ होगा, जिसमें संत-महात्मा श्रद्धालुओं को धर्म, समाज और जीवन के मूल्यों पर मार्गदर्शन देंगे। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिदिन शाम 7 से 10 बजे तक संध्या आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आयोजन समिति द्वारा प्रतिदिन विशाल भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है।श्रद्धालुओं का उत्साह, भजन-कीर्तन की गूंज और धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला ने इस वारूनी महामेला को एक यादगार आध्यात्मिक पर्व बना दिया है।

एसईसीएल ऑफिसर कॉलोनी के पास से हटाया गया अवैध अतिक्रमण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल के सुरक्षा विभाग ने ऑफिसर कॉलोनी के पास किए गए अतिक्रमण को मंगलवार सुरक्षा विभाग द्वारा हटवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसईसीएल की लीज भूमि पर आएदिन अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रहती हैं। ऑफिसर कॉलोनी के आसपास खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर अस्थायी निर्माण और घेराबंदी की गई थी। मंगलवार को एसईसीएल सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंच अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया।सूत्रों के अनुसार एसईसीएल की जमीन पर यह

कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन अलग-अलग स्थानों पर लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कई बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं रुक रहा, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया जाता है।एसईसीएल प्रबंधन ने कहा है कि कंपनी की लीज भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाही बरतने पर प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षक निलंबित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विकासखण्ड वाड्रफनगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गैना के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) खितेश कुमार पटेल के द्वारा 25 एवं 26 फरवरी 2026 को बगैर किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति प्राप्त किए बिना शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया।

इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला गैना में पदस्थ प्रधानपाठक श्रीमती अनिता पटेल बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृत अवकास के विद्यालय से अनुपस्थित पाई गई। जिसपर खितेश कुमार पटेल और अनिता पटेल को कारण बताओ सूचना जारी किया गया। दोनों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण एवं परिशीलन करने पर प्रति उतर एवं असंतोषजनक पाया गया। जिससे निरीक्षण तिथि पर उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया सही होना पाया गया। जो कि शासकीय सेवा के कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 स्पष्ट उल्लंघन है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सहायक शिक्षक खितेश कुमार पटेल एवं प्रधानपाठक अनिता पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचन्द्रपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

मिलेट्स के पोषण गुणों से विद्यार्थियों को अवगत कराने महाविद्यालय में हुआ श्री अन्न फूड फेस्टिवल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। मंगलवार को यहां रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय में श्री अन्न फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर के कुलसचिव डॉ.एस.पी. त्रिपाठी रहे। फेस्टिवल के अंतर्गत महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मिलेट्स उत्पादों एवं मिलेट्स से निर्मित विविध खाद्य पदार्थों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि डॉ. त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में बताया कि वे स्वयं अपने दैनिक जीवन में मिलेट्स का नियमित उपयोग करते हैं और आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसानों से मिलकर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मिलेट्स का उपयोग अत्यंत आवश्यक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर अनेक बीमारियों से रक्षा करता है। बीज वक्ता के रूप में शासकीय राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के कृषि विभाग के डीन डॉ.एस.के. सिन्हा ने मिलेट्स की कृषि परंपरा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मिलेट्स लगभग 7 हजार वर्ष पुरानी कृषि परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। गेहूँ और चावल की तुलना में 70 प्रतिशत कम पानी में तैयार होने वाली यह फसल सूखा, गर्मी और कम

उपजाऊ मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। इसकी खेती में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही यह भूमि क्षरण को रोककर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। मुख्य वक्ताओं के रूप में नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर की प्राचार्य डॉ. आर.एन. कच्छप एवं डॉ. महेश मिश्रा ने मिलेट्स को आधुनिक पोषण विज्ञान में सुपरफूड की श्रेणी में रखे जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिलेट्स में गेहूँ और चावल की तुलना में दोगुने से अधिक प्रोटीन एवं तीन गुना फाइबर होता है। इसके अतिरिक्त काबोर्हाइड्रेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन एवं एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह ग्लूटेन मुक्त और प्रीबायोटिक गुणों से युक्त है, जो आंतों के स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करता है। बाजरा, रागी, कंगनी, सामा, कोदो, कुटकी, ज्वार सहित 150 से अधिक प्रकार के श्री अन्न इसी श्रेणी में आते हैं। फेस्टिवल का विशेष आकर्षण रहा कोरिया मिलेट्स कैफे, जिसकी संचालक सुश्री हिना, यासमीन एवं उनकी टीम ने रागी चीला, ज्वार चीला, मिलेट्स मंचूरियन, कोदो खीर, ज्वार गुलाब जामुन, रागी मिक्सचर, रागी-ज्वार-बाजरा कुकीज एवं लड्डू जैसे स्वादिष्ट व्यंजन प्रदर्शित किए और उनकी संपूर्ण निर्माण विधि से प्रतिभागियों को अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कोरिया मिलेट्स कैफे की सराहना की है। समूह प्रमुख सुश्री हिना ने जानकारी दी कि वर्ष 2023 में स्थापित इस कैफे ने अब तक लगभग 2 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 62 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 31 महिलाओं का यह समूह मिलेट्स आधारित स्वादिष्ट एवं पौष्टिक व्यंजन तैयार करने में सक्रिय है। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, जिला कोषालय अधिकारी श्री तिवारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग घनश्याम सांडिल्य सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एच.एन. दुबे के नेतृत्व में कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. प्रतिभा कश्यप, डॉ. अखिलेश द्विवेदी, डॉ.विकेश झा, टी.आर. राहंगडाले, डॉ.चंदन कुमार सहित समस्त प्राध्यापकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन अखिलेश पाण्डेय ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. प्रतिभा कश्यप द्वारा किया गया।

समभाव महिला मंच ने किया रोजा इफ्तार का आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। समभाव महिला मंच द्वारा प्रतिवर्ष की भांति वर्ष इस वर्ष भी रोजा इफ्तार 2026 कार्यक्रम का आयोजन होटल अलंकार ग्रीन्स में किया गया। कार्यक्रम में प्रेम, सौहार्द्र, सद्भावना और सामाजिक समरसता की झलक देखने को मिली। रोजा इफ्तार कार्यक्रम में समभाव की सदस्य बहनों के अलावा शहर से अन्य रोजेदार बहनें भी शामिल रहीं। सर्व समाज के महिलाओं की सहभागिता से यह आयोजन प्रेरक रहा। समभाव महिला मंच की सूत्रधार और संस्थापिका वंदना दत्ता सहित मंच की सभी सदस्यों के आपसी समन्वय से आयोजन सफल रहा। इस मौके पर अतिथि के रूप में डॉ. पुष्पा सोनी और पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. जसमीत ढिल्लो की उपस्थिति रही। इन्होंने कहा कि एक बड़े समूह में किसी भी आयोजन की निरंतरता बनाए रखना आपसी सामंजस्य और सकारात्मक विचारधारा को प्रदर्शित करता है। समभाव महिला मंच के आयोजन में इसकी मिसाल स्पष्ट परिलक्षित होती है। अतिथियों ने समभाव के पहल की प्रशंसा की और सभी ने ईद और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। बता दें कि समभाव महिला मंच अंबिकापुर नगर में 16 दिसंबर 2015 से कौमी एकता की मिसाल बनकर सामने आया है। मंच की संस्थापिका वंदना दत्ता ने समभाव महिला मंच स्थापना और प्रथम बैठक को याद करते हुए इससे जुड़ी कई सुनहरी यादों को उपस्थित लोगों के समक्ष साझा किया। उन्होंने कहा कि सभी समाज का ये साझा मंच समय-समय पर नगर व पूरे समाज में सद्भावना और भाईचारे का संदेश प्रसारित करता रहा है, आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। समाज में कौमी एकता का खूबसूरत पैगाम खुशबू की तरह फैलता रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. शबनम खानम ने किया। अंजुम शमीम, रुही गजाला, लिलि कहकशा, नुजहत फातिमा, शिरीन खान ने रमजान पर्व को लेकर अपनी-अपनी बातें रखी। वरिष्ठ सदस्य सन्तोस पांडे एवं समाज की वरिष्ठ सदस्य रूबी सिद्दीकी ने बताया कि सर्व समाज की बहनों के साथ रोजा इफ्तार केवल जैसा वृहद आयोजन अंबिकापुर में ही निरन्तर हो रहा है। नॉशाबा, सरीफुन और अन्य मुस्लिम बहनों ने एक साथ नमाज अता करके मिलकर रोजा इफ्तार किया। आभार प्रदर्शन हिना परवीन ने किया। जरूरतमंदों के लिए मुस्लिम बहनों ने मिलकर जकात भी दिया। समभाव का आगामी आयोजन नवरात्रि पर व्रती बहनों के लिए होगा। इस मौके पर मंदिरों में फलाहार का वितरण, 22 मार्च और 24 मार्च को 4 समूहों में 4 स्थलों पर किया जाएगा।

जिला अस्पताल में शुरू हुआ एचपीवी टीकाकरण अभियान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने की दिशा में जिले ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर एस.जयवर्धन के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में यहां जिला चिकित्सालय में 14 वर्ष की किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाकर जिले में इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा यह विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खडगांवां से मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया। इसी कड़ी में सोमवार 16 मार्च को सूरजपुर जिले में भी यह अभियान प्रारंभ हो गया है। जिला चिकित्सालय स्थित सौ बिस्तरीय मातृत्व एवं शिशु अस्पताल के टीकाकरण कक्ष में प्रतिदिन प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक यह टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं, बल्कि एक विशेष राष्ट्रीय अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को गार्डासिल नामक क्वाड्रिवैलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक खुराक दी जाएगी, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। शुभारंभ कार्यक्रम में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ.अजय मरकाम, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. प्रियंका पटेल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.आरआरएस सिंह, उपेंद्र सिंह, सतेंद्र खुटे, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कुसुम, विमला स्वामी, मंजू, ममता, संदीप गुप्ता एवं मितानिन बहनें उपस्थित रहीं।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजगंज। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामानुजगंज के अध्यक्ष मधु गुप्ता के नेतृत्व में जिला और ब्लॉक ईस्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए एसआईआर पश्चात मतदाता सूची के अंतिम प्रकाश उपरांत प्रारूप-07 के माध्यम से नाम विलोपन के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई है। सौंपे पर गए ज्ञापन में कहा गया है कि छ.ग.राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची में वर्ष 2003 के पश्चात मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम यथावत रखा गया और निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रक्रियायें पूर्ण किया गय तब जाकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद राष्ट्रीय पाटीर्यों को मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई है। लेकिन रामानुजगंज विधानसभा के मतदाता केन्द्रो पर भाजपा के कई कार्यकर्ता एंव पदाधिकारीयो के द्वारा विशेष रूप वर्ग विशेष समुदाय एवं कांग्रेस समर्थीत लोगो का प्रारूप 07 का फार्म भरकर प्रायोजीत तरीके से जमा किया गया है। उस पर उचित कार्यवाही की मांग करते है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस मतदान केन्द्र में निवास नही करता है उस व्यक्ति के द्वारा यदि नाम विलोपित करने का फार्म भरकर दिया गया है तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, व्ही कुछ-कुछ मतदान केन्द्रो में दूसरे के नाम से फार्म भरकर नाम काटने का आवेदन दिया गया है, उस व्यक्ति से पूछने पर कहा गया कि हमने आवेदन ही नही दिया है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल चिन्हित कर कानुनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। अवलोकन हेतु मतदान केंद्र वार भरे गए प्रारूप-7 का सूची मांगी गई है। इस विषय में ब्लॉक अध्यक्ष माधुरी गुप्ता का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत प्रशासनिक तंत्र के द्वारा पूर्ण किए गए प्रक्रिया में यदि स्वार्थी तत्व अपना मतलब साधना चाहते हैं तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी उपलब्ध कराने के बाद भी प्रशासनिक तंत्र यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो इसके लिए सम्मिलित व्यक्तियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी बाध्य होगी जिसकी जवाब देहि जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर अजय कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष अजय सोनी महामंत्री मनोज दुबे सुधा जायसवाल व्यास मुनि यादव जिला सचिव प्रतीक सिंह अशोक गौड़ नीरज गुप्ता प्रेम सागर सिंह मंडल अध्यक्ष नौशाद आलम मंडल अध्यक्ष चंदेश्वर कुशवाह मंडल अध्यक्ष जौन कुस मंडल अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी मोहम्मद खलीफा ओम प्रकाश यादव सहित सैकड़ो की संख्या में कांग्रेसी जन उपस्थित रहे।

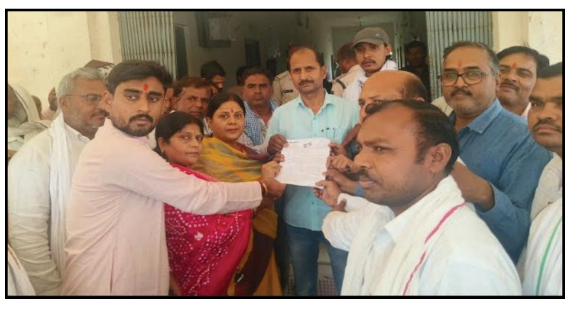

कलेक्ट्रेट परिसर के सभागृह में विश्व उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम आयोजित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। विश्व उपभोक्ता दिवस का कार्यकम कलेक्ट्रेट परिसर के कम्पोजिट बिल्डिंग के सभागृह में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के एवं वक्ता के रूप में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जिसमें प्रशिक्षण एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं ई-जागृति एवं ई-हियरिंग तथा ऑन लाईन प्रकरण प्रस्तुत करना एवं सुनवाई कराये जाने के संबंध में जागरूक किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में खाद्य विभाग के अधिकारी, एवं शासन के अन्य अधिकारी के अतिरिक्त लगभग 150 शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे। जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अम्बिकापुर के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के साथ, प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की प्रकिया एवं प्रकरण प्रस्तुत करने में बरती जाने वाली सावधानियां, आर्थिक एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही ई-जागृति के माध्यम ऑन लाईन फाईलिंग किये जाने के संबंध में भी जानकारी दिया गया। कार्यक्रम का संचालन खाद्य विभाग के अतिरिक्त खाद्य अधिकारी के द्वारा किया गया।

वार्षिक उत्सव के साथ मना विश्व उपभोक्ता दिवस

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम के साथ विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा-अम्बिकापुर के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता के अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ई-जागृति व ई-हियरिंग तथा ऑन लाईन प्रकरण प्रस्तुत करना एवं सुनवाई कराये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय परिसर के प्राचार्य, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं लगभग 300 छात्र-छात्राओं तथा स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहें। कार्यक्रम पश्चात मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को मेडल एवं प्रमाण-पत्र वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से सुनिता के चेहरे पर लौटी मुस्कान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम नागरिकों को बकाया बिजली बिल में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जो आर्थिक तंगी के कारण लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे और बढ़ते बकाया, ब्याज एवं सरचार्ज के कारण मानसिक एवं आर्थिक दबाव झेल रहे थे। इसी क्रम में अम्बिकापुर विकासखंड के पोड़ी ग्राम पंचायत की निवासी श्रीमती सुनीता के जीवन में इस योजना ने नई उम्मीद जगाई है। सालों से बकाया बिजली बिल की चिंता में डूबी सुनीता को जब योजना का लाभ मिला, तो उनके चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव नजर आया।

प्रकरण का निराकरण कर बकाया बिल में मिली 75% तक की छूट

हितग्राही श्रीमती सुनीता ने बताया कि उनके घर का बिजली बिल बढ़ते-बढ़ते 19,970 रुपए तक पहुंच गया था। सीमित आय और ग्रामीण परिवेश के कारण इतनी बड़ी राशि एकमुश्त जमा करना उनके लिए संभव नहीं था। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत उनके प्रकरण का त्वरित निराकरण किया गया और उन्हें लगभग 75 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की गई, जिससे उन्होंने मात्र 6,200 रुपए जमा कर अपना बकाया बिल चुकता कर लिया।

शासन की योजना के लिए जताया आभार

श्रीमती सुनीता ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ते बिजली बिल को लेकर वे लगातार चिंतित रहती थीं और बिजली कटने का भय भी बना रहता था। योजना के माध्यम से मिली छूट ने उनकी चिंता को दूर कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिली है और अब वे निश्चिंत महसूस कर रही हैं।

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 का उद्देश्य ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है, जो विभिन्न कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। योजना के माध्यम से ब्याज एवं सरचार्ज में छूट देकर उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है, जिससे न केवल बकाया राशि की वसूली हो रही है, बल्कि आमजन के घरों में विद्युत आपूर्ति भी सुचारू बनी हुई है।

कार्यपालन अभियंता ने दी योजना की जानकारी

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता रोशन नागवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 12 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2023 की स्थिति में जिन उपभोक्ताओं की राशि बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि इच्छुक उपभोक्ता मोर बिजली ऐप के माध्यम से स्वयं का पंजीयन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, जो उपभोक्ता डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वे सीधे विभागीय कार्यालय में आकर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल सुशासन एवं अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश के हजारों परिवारों को राहत प्रदान कर रही है। जिससे सुनीता की तरह अब बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल से मुक्ति मिलेगी।

सम्पादकीय

अब होगी नेताओं के दावों की परीक्षा

देश के पांच राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सत्ता की दौड़ तेज होगी। नेताओं के बड़े-बड़े दावे जनता की कसौटी पर परखे जाएंगे। करीब 17.4 करोड़ मतदाताओं और 824 विधानसभा सीटों पर होने वाला यह चुनाव केवल सरकार बदलने का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की परिपक्वता और जनता की उम्मीदों की भी बड़ी परीक्षा है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों ने अपने-अपने एजेंडे, वादों और रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। इन चुनावों की खास बात यह है कि यहां राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा तीखी रही है, जहां क्षेत्रीय दलों की मजबूत पकड़ है। ऐसे में राष्ट्रीय दल भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। चुनावों के दौरान अक्सर नेताओं द्वारा विकास, रोजगार, महंगाई और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। मुफ्त योजनाओं और जनहित के नाम पर नई-नई घोषणाएं मतदाताओं को प्रभावित करने का एक प्रमुख माध्यम बन जाती हैं, लेकिन समय के साथ मतदाताओं की समझ भी परिपक्व हुई है। अब मतदाता केवल वादों और नारों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे यह भी देखते हैं कि पिछले कार्यकाल में सरकारों ने वास्तव में क्या काम किया है और जनता के जीवन में कितना बदलाव आया है। यही वजह है कि यह चुनाव नेताओं के दावों की असली परीक्षा बनकर सामने आएगा। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि आचार संहिता लागू होने के बाद अब कोई भी सरकार नई योजनाओं या घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है। चुनाव केवल नेताओं या राजनीतिक दलों की परीक्षा नहीं होते, बल्कि यह मतदाताओं की जिम्मेदारी और जागरूकता की भी कसौटी होते हैं। जब मतदाता अपने अधिकार का ईमानदारी से प्रयोग करते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए जरूरी है कि हर मतदाता इस लोकतांत्रिक पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले और अपने वोट का प्रयोग जरूर करे। आखिरकार, चुनाव केवल सत्ता हासिल करने की दौड़ नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को जीतने की प्रक्रिया भी है। नेताओं के लिए यह अवसर है कि वे केवल वादे करने तक सीमित न रहें, बल्कि जनता के भरोसे को निभाने का संकल्प भी दिखाएं क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास ही होता है। मई में आने वाला जनादेश किसे सत्ता की जिम्मेदारी सौंपता है। जनता के लिए भी यह जिम्मेदारी के साथ चुनाव करने का मौका है। लोकतंत्र का यह उत्सव आखिर जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का आईना बनकर सामने आएगा।

डोनाल्ड ट्रंप के दावे और टूटता तिलिस्म

विश्लेषण
महेन्द्र तिवारी

ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और उनके आक्रामक व्यापारिक दृष्टिकोण ने वैश्विक भू-राजनीति में भारत और अमेरिका के संबंधों को एक जटिल धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के घटनाक्रम और ट्रंप के बयानों से यह आभास होता है कि वे भारत के आर्थिक उभार को एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, विशेषकर जब वे सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि वे भारत को 'अगला चीन' नहीं बनने देंगे। हालांकि, उनकी रणनीति का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के संदर्भ में अमेरिकी दबाव की सीमाएं बहुत संकीर्ण हैं। ट्रंप का यह सोचना कि प्रतिबंधों की धमकी से भारत की विकास यात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जमीनी हकीकत से परे नजर आता है।

डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और उनके आक्रामक व्यापारिक दृष्टिकोण ने वैश्विक भू-राजनीति में भारत और अमेरिका के संबंधों को एक जटिल धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के घटनाक्रम और ट्रंप के बयानों से यह आभास होता है कि वे भारत के आर्थिक उभार को एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, विशेषकर जब वे सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि वे भारत को 'अगला चीन' नहीं बनने देंगे। हालांकि, इस दावे और भारत पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के संदर्भ में अमेरिकी दबाव की सीमाएं बहुत संकीर्ण हैं।

ट्रंप का यह सोचना कि टैरिफ युद्ध या प्रतिबंधों की धमकी से भारत की विकास यात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जमीनी हकीकत से परे नजर आता है। भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा, चाहे वह व्यापारिक नीतियां हों या रूस जैसे देशों के साथ ऊर्जा संबंध। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर टैरिफ हमलों की श्रृंखला तब शुरू हुई, जब अमेरिका ने भारत को 'टैरिफ किंग' करार दिया और हार्ले-डेविडसन जैसी मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क को लेकर कड़ा रुख अपनाया। जवाब में, अमेरिका ने भारत को मिलने वाले 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस' (जीएसपी) के लाभ को समाप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को चोट पहुंचाना था, लेकिन इसके परिणाम ट्रंप की उम्मीदों के विपरीत रहे। भारत ने न केवल अमेरिकी कृषि उत्पादों और बादाम जैसे आयातों पर जवाबी शुल्क लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा की, बल्कि अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण भी शुरू कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बावजूद, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि देखी गई, जो यह दर्शाता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर इस कदर निर्भर हैं कि केवल टैरिफ के जरिए इन्हें अलग करना या भारत को दबाना संभव नहीं है।

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत एक अपरिहार्य बाजार और विनिर्माण केंद्र बना हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना खुद अमेरिका के लिए आर्थिक आत्मघात जैसा होगा। दबाव की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान देखने को मिला, जब अमेरिका ने भारत पर रूस से कच्चा तेल न खरीदने और प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भारी राजनयिक दबाव डाला। ट्रंप और उनके समर्थक गुट का मानना था कि भारत को अमेरिकी छत्रछाया में लाने के लिए यह सही समय है। हालांकि, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए न केवल रूस से तेल की खरीद जारी रखी, बल्कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक अवसर में बदल दिया।

अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और 'प्राइस कैप' जैसी नीतियों को दरकिनार करते हुए भारत ने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप फैसले लिए। यह अमेरिकी कूटनीति की एक बड़ी विफलता मानी जा सकती है क्योंकि वह एक प्रमुख लोकतांत्रिक साझेदार को अपनी मर्जी के अनुसार झुकने पर मजबूर नहीं कर सका। भारत के इस कड़े रुख

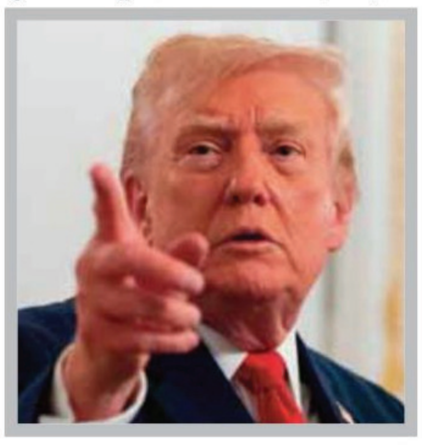

ने स्पष्ट कर दिया कि नई दिल्ली की विदेश नीति अब वाशिंगटन के निर्देशों पर नहीं, बल्कि अपने 140 करोड़ नागरिकों की जरूरतों और वैश्विक स्थिरता के अपने दृष्टिकोण पर आधारित है।

भारत की तुलना चीन से करना और उसे 'अगला चीन' न बनने देने की बात करना ट्रंप की एक रणनीतिक भूल को दर्शाता है। चीन का उदय एक सत्तावादी ढांचे के तहत हुआ, जिसने वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करती है। ट्रंप का यह डर कि भारत अमेरिकी विनिर्माण को निगल जाएगा, तथ्यात्मक रूप से कमजोर है क्योंकि भारत का विकास मॉडल निर्यात-आधारित होने के साथ-साथ उपभोग-आधारित भी है। भारत आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर रहा है, जिसे अमेरिका खुद 'फ्रेंड-शोरिंग' के नाम से बढ़ावा देता रहा है। ऐसे में एक तरफ भारत को विनिर्माण का विकल्प बनाना और दूसरी तरफ उसकी प्रगति को रोकने की बात करना ट्रंप की नीतियों में गहरे अंतर्विरोध को उजागर करता है। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यह भी देखा गया कि रक्षा सौदों के मामले में भी अमेरिका का दबाव काम नहीं आया। भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली का सौदा किया, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। भारत का अडिग रहना और अंततः अमेरिका का प्रतिबंधों से पीछे हटना यह साबित करता है कि वाशिंगटन को भारत की सैन्य और सामरिक महत्ता का भली-भांति आभास है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जितनी आवश्यकता है, उतनी भारत को अमेरिका की नहीं।

यह शक्ति संतुलन ट्रंप के उन दावों को खोखला कर देता है, जिनमें वे भारत को नियंत्रित करने की बात करते हैं। भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलें किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी क्षमता विस्तार के लिए हैं और ट्रंप के टैरिफ या धमकियां इसे रोकने में अक्षम साबित हुई हैं। अंततः ट्रंप की रणनीति में एक बुनियादी कमी यह है कि वे भारत को केवल एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं, जबकि भारत एक सभ्यतागत शक्ति और उभरता हुआ वैश्विक ध्रुव है। भारत की डिजिटल क्रांति, उसका विशाल युवा कार्यबल और उसकी रणनीतिक स्थिति उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर ले जा रही है। ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' के मुकाबले भारत का 'सबका साथ, सबका विकास' और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने का संकल्प अधिक समावेशी और प्रभावी है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप द्वारा भारत पर बनाए गए दबाव के हर प्रयास ने भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनने और अपने विकल्पों को तलाशने के लिए प्रेरित किया है। भारत को दबाव में रखकर सफल होने का सपना देखने वाले नेताओं को यह समझना होगा कि 21वीं सदी का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है और किसी भी महाशक्ति का कनिष्ठ भागीदार बनने के बजाय एक समान और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ट्रंप के दावे महज चुनावी बयानबाजी या दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक विश्व व्यवस्था में भारत की गति को रोकना अब किसी भी एक शक्ति के बस की बात नहीं रह गई है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

दिवस विशेष
श्वेता गोयल

मानवता का सबसे सशक्त सुरक्षा कवच है टीकाकरण

मानव सभ्यता के इतिहास में अदृश्य सूक्ष्मजीवों, वायरसों और जीवाणुओं ने समय-समय पर अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौतियां पेश की हैं। इन प्राणघातक संकटों के विरुद्ध मानवता के पास सबसे सशक्त और अचूक अस्त्र 'टीकाकरण' ही रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाने वाला 'राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस' सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक चेतना और लाखों जिंदगियों को अकाल मृत्यु से बचाने के संकल्प का उत्सव है। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि कैसे विज्ञान ने प्रकृति के प्रकोप को नियंत्रित कर एक स्वस्थ समाज की नींव रखी है। टीकाकरण की महत्ता को समझना आज इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि यह न केवल व्यक्ति विशेष की रक्षा करता है बल्कि एक अभेद्य सामुदायिक सुरक्षा तंत्र (हर्ड इम्यूनिटी) का निर्माण भी करता है। टीकाकरण की प्रक्रिया वास्तव में शरीर की आंतरिक रक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने की एक कला है। हमारे वातावरण में अनगिनत रोगजनक तत्व विचरण करते हैं, जो किसी भी क्षण हमें अपनी चपेट में ले सकते हैं। वैक्सीन इन खतरों के विरुद्ध शरीर में एक कृत्रिम प्रतिरक्षा जागृत करती है, जिससे हमारा शरीर वास्तविक संक्रमण होने पर उससे लड़ने के लिए पहले ही तैयार रहता है। यह चिकित्सा विज्ञान की वह अद्भुत उपलब्धि है, जिसने चेचक जैसी भयावह बीमारियों का नामोनिशान मिटा दिया और पोलियो जैसे अभिशाप को इतिहास के पन्नों तक सीमित कर दिया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का मूल ध्येय समाज के हर वर्ग, विशेषकर नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस अभियान की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है। यह उन अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, डॉक्टरों और नर्सों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी क्षण है, जो दुर्गम क्षेत्रों में जाकर हर बच्चे तक 'सुरक्षा की खुराक' पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में टीकाकरण की ऐतिहासिक विजय गाथा का विश्लेषण करें तो 16 मार्च की तिथि स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी दिन वर्ष 1995 में देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, जो 'पल्स पोलियो अभियान' के व्यापक शंखनाद का प्रतीक बनी। 'दो बूंद जिंदगी की' का वह नारा केवल एक विज्ञापन नहीं बल्कि एक जन-आंदोलन बन गया, जिसने देश के कोने-कोने में चेतना जगाई। उस समय भारत पोलियो के मामलों का प्रमुख केंद्र माना जाता था लेकिन निरंतर प्रयासों और टीकाकरण की शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल में अंतिम मामला मिलने के बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया। यह उपलब्धि प्रमाणित करती है कि यदि इच्छाशक्ति और टीकाकरण का सही समन्वय हो तो किसी भी महामारी को परास्त किया जा सकता है। टीकाकरण की प्रासंगिकता केवल शिशुओं तक सीमित नहीं है। यद्यपि इसका आरंभ बाल्यकाल की सुरक्षा से होता है परंतु व्यस्क और वृद्धजनों के लिए भी यह उतना ही अनिवार्य है। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इस सत्य को वैश्विक स्तर पर पुनर्स्थापित किया है। 2020 के बाद भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर यह सिद्ध किया कि आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना केवल वैज्ञानिक नवाचार से ही संभव है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि टीकाकरण के लाभ केवल व्यक्तिगत आरोग्य तक सीमित नहीं रहते बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ कार्यबल राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति देता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में टीकाकरण की जड़ें बहुत गहरी हैं। दस्तावेजी प्रमाण बताते हैं कि 1802 में मुंबई की एक नन्ही बालिका को चेचक का टीका लगाकर इस आधुनिक सुरक्षा चक्र की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1896 में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम का आना और 20वीं सदी के प्रारंभ तक हैजा, प्लेग और टाइफाइड जैसी महामारियों के विरुद्ध टीकों की उपलब्धता ने भारतीय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान की। टीकाकरण केवल दवा की बूंद नहीं है बल्कि यह एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की पहली शर्त है। आज जब हम आधुनिक प्रौद्योगिकियों के युग में जी रहे हैं, तब हमारा यह दायित्व है कि हम भ्रांतियों और अफवाहों को दरकिनार कर टीकाकरण को एक नागरिक कर्तव्य के रूप में अपनाएं। यदि हम 'पूर्ण टीकाकरण' के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो भविष्य की पीढ़ियों को हम एक रोगमुक्त और निर्भय संसार उपहार में दे सकेंगे। हर साल लाखों जिंदगियां बचाने का यह संकल्प तभी फलीभूत होगा, जब 'सुरक्षा का यह चक्र' समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

(लेखिका शिक्षिका हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

ईश्वर की प्राप्ति

जड़ जगत की रचना के लिए ईश्वर की जो शक्ति काम करती है, उसे प्रकृति कहते हैं और चैतन्य जगत की रचना करने वाली शक्ति को जीव कहते हैं। जिस प्रकार दोनों हाथ एक ही शरीर के दो भाग हैं, उसी प्रकार जीव और प्रकृति दोनों ही ईश्वरतत्व के दो अंश हैं। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, असल में वह अखिल आद्यशक्ति का सतोगुणी अंश है। मानवीय उन्नति तो सत्व गुणों को प्राप्त करने से ही हो सकती है। इसलिए उन उच्च गुणों की एक मानसिक प्रतिमा बनाकर उपासना करने का विधान किया गया है। ईश्वर का सत्व गुण अदृश्य रूप से हमारे निकट ही वर्तमान है। उसे अधिक मात्र में खींचकर अपने अंदर भर लेने के लिए प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और ध्यान अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन्हीं चारों के समन्वय को 'उपासना' कहा जाता है। उपासना जितनी ही प्रबल होगी, आकर्षण भी वैसा ही सशक्त होगा और उसी के अनुसार उपास्य देवतत्व की प्राप्ति होगी। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, त्याग, समता और न्याय आदि सद्गुणों का निष्ठापूर्वक जितना अधिक चिंतन किया जाता है, उतनी अधिक उनकी प्राप्ति होती है। उन्नति का क्रम तम से सत की ओर चलना है। जिसने जितना ही सतुण अपने में धारण कर लिया, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही उन्नतिशील कहा जाएगा। यदि एक भक्त सत तत्व की उपासना करता है तो कोई कारण नहीं कि उसे वह प्राप्त न हो। ईश्वर की उपासना का तात्पर्य उसके दिव्य सत तत्व की आराधना है।

संकलित
दर्शन

दूसरों को कमजोर समझने की गलती न करें

महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने-सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र-शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब-जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब-जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्रीकृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण ये रथ पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। यदि ये न होता तो पता नहीं तुम्हारे रथ की क्या स्थिति होती। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का अहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। यथा स्थिति का अच्छा से अवलोकन करे।

संकलित
प्रेरणा

अंतर्मन

आज की पाती

बड़ा बोझ क्यों बन रही शादियां?

भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक आयोजन भी माना जाता है। यहां शादी में परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और पूरा समाज शामिल होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शादियों का स्वरूप बहुत बदल गया है। आजकल कई शादियां इतनी भव्य और महंगी हो गई हैं कि उनमें करोड़ों रुपए तक खर्च किए जाते हैं। बड़े-बड़े होटल, महंगे कपड़े, विदेशी सजावट, मशहूर कलाकारों के कार्यक्रम और कई दिनों तक चलने वाले समारोह अब आम बात हो गए हैं। ऐसी शादियों का सबसे बड़ा प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है। जब समाज में अमीर लोग बहुत महंगी शादियां करते हैं तो बाकी लोगों पर भी वैसी ही शादी करने का दबाव बनने लगता है। आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च बोझ बन जाता है।

– मनीराम बहलान, सिरसा

करंट अफेयर

हमलों के बाद 'काली बारिश' से ईरान की जनता को खतरा

अमेरिका व इजराइल के ईरान के तेल भंडारों पर किये गये हवाई हमलों कारण उठे जहरीले धुएं के बादल धरती पर 'काली बारिश' हुई। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसके मद्देनजर जनता के लिए गंभीर खतरों की चेतावनी जारी की है।

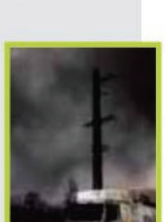

पिछले हफ्ते ईरान के कई तेल डिपो और एक रिफाइनरी पर हमले के बाद तेहरान के पास काली और तैलीय बारिश हुई, जिससे राजधानी के निवासियों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। दो सप्ताह से जारी युद्ध के दौरान क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी काले धुएं के गुबार देखे गए। ईरान भी फारस की खाड़ी के पड़ोसी देशों के तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों पर ड्रोन व मिसाइलों से हमला कर अमेरिकी-इजराइली हवाई हमलों का जवाब दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, बारिश अपेक्षाकृत कम समय में वायुमंडल से खतरनाक रसायनों को साफ कर देती है लेकिन काली बारिश के संपर्क में आने वाले लोगों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यह तब होता है, जब राख और जहरीले रसायन वायुमंडल में पानी की बूंदों के साथ मिलकर बारिश के दौरान वापस पृथ्वी पर गिरते हैं। तेल रिफाइनरियों या तेल क्षेत्रों में आग लगने के बाद यह आम बात है।

ऑफ बीट

ब्रह्माण्ड स्वयं को क्यों खंडित कर रहा

ब्रह्मांड किससे बना है? यह प्रश्न सैकड़ों वर्षों से खगोलविदों को उद्वेलित करता रहा है। पिछली एक चौथाई सदी से, वैज्ञानिकों का मानना है कि परमाणु

और अणु जैसी 'सामान्य' चीजें जो आपको, मुझे, पृथ्वी और लगभग हर चीज को बनाती हैं जिसे हम देख सकते हैं, ब्रह्मांड का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा है। अन्य 25 प्रतिशत 'डार्क मैटर' है, एक अज्ञात पदार्थ जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम यह पता लगा सकते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सामान्य पदार्थ को कैसे प्रभावित करता है। ब्रह्मांड का शेष 70 प्रतिशत भाग 'डार्क एनर्जी' से बना है। 1998 में खोजा गया, यह ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का लगातार बढ़ती दर से विस्तार कर रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में जल्द ही प्रकाशित होने वाले एक नए अध्ययन में, हमने डार्क एनर्जी के गुणों को पहले से कहीं अधिक विस्तार से मापा है। हमारे नतीजे दिखाते हैं कि यह एक काल्पनिक वैक्यूम ऊर्जा हो सकती है जिसके बारे में सबसे पहले आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया था – या यह कुछ अजीब और अधिक जटिल हो सकता है जो समय के साथ बदलता रहता है। एक सदी पहले जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत विकसित किया।

ट्रेंड

जनता देगी जवाब

टीएमसी वालों को यह याद रखना होगा कि उन्होंने केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी का अपमान नहीं किया है, बल्कि देश के आदिवासी समाज के साथ-साथ करोड़ों महिलाओं के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। पश्चिम बंगाल की जनता-जनार्दन इसका भरपूर जवाब देगी।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कांशीराम को मिले भारत रत्न

सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कांशीराम के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक़ और आत्मसम्मान की राह दिखाई।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

ब्याज-मुक्त ऋण

युवा शक्ति ही सशक्त राजस्थान की असली पहचान है। उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज-मुक्त ऋण दिया जा रहा है।

- भजनलाल शर्मा, सीएम, राजस्थान

डबल इंजन सरकार

कुछ साल पहले किसने सोचा होगा कि असम के हर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल होगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और एम्स होंगे, एक पानी के नीचे सुरंग होगी और भी बहुत कुछ। डबल इंजन सरकार ने इन सभी को हकीकत बना दिया है।

-हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम, असम

खबर संक्षेप

बीडीएस डिग्री धारक हारिश निकला संदिग्ध आतंकी

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन आईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हारिश अली के रूप में हुई है, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीडीएस की पढ़ाई पूरी की थी। एटीएस के अनुसार हारिश कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने व नए लोगों को संगठन में भर्ती करने के लिए सक्रिय था।

27 के रण में सुभासपा 62 सीटों पर ठोंकेगी दावा

लखनऊ। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 27 के रण में एनडीए गठबंधन में प्रदेश की 62 सीटों पर अपनी पार्टी का दावा ठोंकने के संकेत दिए हैं। कहा कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर तैयारी कर रही है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में चुर्क में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न

सोनभद्र। पुलिस लाइन चुर्क कांफ्रेन्स हॉल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया, तत्पश्चात मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष एवं शाखा प्रभारीगण उपस्थित रहे सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा उनके त्वरित एवं न्यायसंगत निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

जौहर वीरांगनाओं को किया नमन

रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा- संग्रह की भावना छोड़कर दूसरों तक पहुंचाने का भाव अपनाएं

एजेंसी ▸▸ लखनऊ

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर जालौर में हैं। यहां उन्होंने सिरे धाम में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया. इस अवसर पर आयोजित महायज्ञ में उन्होंने पूर्णाहुति दी और बाद में सिरे मंदिर के कन्यागिरी प्रांगण में आयोजित विशाल धर्मसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योगी राज बाबा जालंधरनाथ जी की पावन साधना स्थली पर उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है।उन्होंने नाथ परंपरा के वर्तमान अधिपति महंत पीर गंगानाथ जी महाराज का अभिनंदन करते हुए कहा कि उनके सानिध्य में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375 वर्ष पुरानी परंपरा को भव्य रूप से मनाया जा रहा है।

नाथ संप्रदाय से जुड़े संतों और महंतों का उल्लेख

उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को महायज्ञ में सहभागी बनने और पुण्य अर्जित करने का अवसर मिला है। योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय से जुड़े विभिन्न संतों और महंतों का भी सम्मानपूर्वक उल्लेख करते हुए कहा कि इन संतों की साधना और मार्गदर्शन समाज को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक परंपरा से है। यहां के पर्व, त्यौहार, ऋषि-मुनि, संत-महात्मा, किसान, सैनिक, युवा और मातृ शक्ति-इन सभी के योगदान से भारत महान बना है। उन्होंने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और मनुष्य रूप में जन्म लेना उससे भी अधिक दुर्लभ है। दुनिया में दो सौ से अधिक देश हैं, लेकिन भारत जैसा देश कहीं नहीं है।

बंदरों के चौराहे का किया विशेष उल्लेख

अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में बने बंदरों के चौराहे का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में बंदरों के लिए अलग से एक स्थान बनाया गया है, जिसे चौराहा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जब वे वहां पहुंचे तो अनेक बंदर वहां एकत्र हो गए। योगी ने बताया कि उन्होंने एक बंदर को रोटी दी। बंदर ने उसे शांतिपूर्वक बैठकर खाना शुरू किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह संतों की साधना और आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य भी अपने जीवन में लोभ और संग्रह की भावना छोड़कर दूसरों तक पहुंचाने का भाव अपनाए, तो समाज में अशांति और अराजकता समाप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोभ को नियंत्रित करना भी एक प्रकार की साधना है और यह साधना जीवन में अपनाई जानी चाहिए।

सस्ता सामान और सुविधाएं भी मिलेंगी

वकील-डॉक्टर-शिक्षक और पत्रकार को भी आवास

सीएम योगी ने 92 हजार लोगों को घर बनाने के लिए भेजी पहली किस्त

सीएम योगी ने सभी जिलों और नगर विकास विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सस्ते में अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सके इसकी भी व्यवस्था कराएं। मकान के साथ-साथ शौचालय भी बनना चाहिए। बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलना चाहिए। नल से जल की सुविधा का लाभ भी दिलाएं।

एजेंसी ▸▸ लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को प्रदेश के 92 हजार से अधिक शहरी लाभार्थियों को 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' के तहत आवास निर्माण की पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य आयोजन किया गया था।

उन्होंने जिलों व नगर विकास विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि पीएम आवास के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सस्ते में अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सके इसकी भी व्यवस्था कराएं। मकान के साथ-साथ शौचालय भी बनना चाहिए। बिजली कनेक्शन फ्री व नल से जल की सुविधा का लाभ भी इन्हें मिले। इस मौके पर उन्होंने गरीबों के साथ-साथ प्रदेश के वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों व पत्रकारों के लिए भी आवास उपलब्ध करने की बात की।

खास बातें

- 900 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर
- सस्ती व अच्छी क्वालिटी का सामान लोगों को घर बनाने के लिए मिलना चाहिए

घर का काम 75% पूरा होते ही दूसरी किस्त के लिए डिमांड करें

सीएम योगी ने लाभार्थियों से कहा कि घर का काम 75 प्रतिशत पूरा होते ही दूसरी किस्त के लिए डिमांड करें और जिम्मेदार अधिकारी इसे तत्काल दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि मकान का काम तेजी से आगे बढ़ सके। सीएम योगी ने कहा कि अपना घर हर व्यक्ति का सपना होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम करीब 62 लाख परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध कराने की इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। 2017 से पहले प्रदेश सरकार इसका लाभ नहीं दे पा रही थी। इच्छा शक्ति ही नहीं थी। स्वयं का स्वार्थ हावी था। सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में चिंता थी।

यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत देगी योगी सरकार

- यूपीपीसीएल ने कर दी घोषणा

यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार कुछ राहत देने जा रही है। ऐसे उपभोक्ता जिनका माइनस बैलेंस से बिजली कनेक्टशन कट गया है, इनको लेकर यूपीपीसीएल ने बड़ी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ता अभी भी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को समझने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें बिजली उपयोग करने के लिए पहले से रिचार्ज कराना अनिवार्य होता है।

संभल में नमाज और नमाजियों को लेकर

जिला प्रशासन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

एजेंसी ▸▸ प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की एक मस्जिद के मामले में सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ये निर्देश उस समय दिए, जब वह मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने वाले प्रशासनिक आदेश के मामले को सुन रहा था। कोर्ट ने इस दौरान साफ कहा कि नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पक्की की जाए और अगर उस दौरान कोई वाधा डाले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

प्रशासन ने नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने का दिया था निर्देश

उल्लेखनीय है कि संभल के रहने वाले मुनाजिर खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने संभल जिला प्रशासन के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने का निर्देश दिया गया था। इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से कुछ अहम निर्देश जारी किए गए हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने कहा, नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पक्की की जाए. इसी के साथ कोर्ट ने जिला प्रशासन के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें नमाजियों की संख्या सीमित करने का जिक्र था।

प्रशासन पर की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन के रवैये को लेकर भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि अगर एसपी-कलेक्टर को लगता है कि नमाजियों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है और वो उनकी संख्या सीमित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें संभल से अपना ट्रांसफर भी करवा लेना चाहिए।

महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन पर सख्ती

महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए ऐसा कानून आवश्यक

एजेंसी ▸▸ मुंबई

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का नया धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन रोकने वाला बिल खास तौर पर महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए लाया गया है।

सीएम फडणवीस

उन्होंने बताया कि कई मामलों में महिलाओं को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी की जाती है और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह कानून जरूरी है। सीएम फडणवीस ने कहा कि विपक्ष इस मुदे को वोट बैंक की राजनीति के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। अगर विपक्षी दल इस बिल को ठीक से पढ़ेंगे तो उन्हें इसमें किसी समुदाय के खिलाफ कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ जबरदस्ती, लालच या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 में ऐसे धर्म परिवर्तन पर 7 साल तक की जेल और 1 से 5 लाख रुपए तक की कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।

सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति

विपक्ष के 8 निलंबित सांसदों की होगी लोकसभा में वापसी

▸▸ नई दिल्ली

अनैतिक आचरण को लेकर किए गए विपक्ष के 8 सांसदों (कांग्रेस के 7 और सीपीआई (एम) के 1 सांसद) के निलंबन को रद्द करने को लेकर सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सहमति बन गई है। मंगलवार को प्रश्नकाल के तुरंत बाद यह मुद्दा सदन में उठेगा और उसी के साथ ही इन सभी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा और यह सदन की कार्रवाई में पहले की तरह भाग ले सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि सदन की गरिमा और स्थापित परंपरा का सभी सदस्यों द्वारा पालन किया जाएगा। साथ ही सभी यह सुनिश्चित करेंगे की ऐसी घटनाओं की भविष्य में सदन में पुनरावृत्ति न हो। कोई भी सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने वेल में दूसरी ओर (सत्ता पक्ष) नहीं जाएगा। इसके अलावा कागज फाड़कर नहीं फेंके जाएंगे।

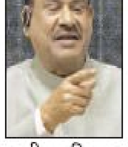

स्पीकर बिरला

कर्नाटक में चेन्नू उत्सव की धूम

मंगलुरु। कर्नाटक के मंगलुरु के पास पोलाली श्री राजा राजेश्वरी मंदिर में वार्षिक उत्सव (चेन्नू) के दौरान, विशेष औपचारिक अनुष्ठानों के बाद स्थानीय लोग देवी भगवती, भद्रकाली और अरासु की पवित्र वस्तुओं को पारंपरिक नावों के माध्यम से फाल्गुनी नदी के पार ले जाते हुए। चेन्नू एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है। पवित्र वस्तुओं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक नाव से ले जाना इस परंपरा का एक प्रमुख आकर्षण है।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क० / अ-63अ/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सुमती पति मधु सरकार, निवासी ग्राम अजिरमा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण के पिता को न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर, जिला सूरजपुर छ०ग० के रा.प्र.क्र.-26/अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 24/01/1994 के अनुसार ग्राम अजिरमा स्थित भूमि खसरा नंबर 286, 302, 304 रकबा कमशः 1.00, 2.60, 2.40 एकड़ कुल रकबा 7.00 एकड़ का पुनर्वास पटटा प्रदान किया गया है। आवेदिका को ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-959129 जारी किया गया है। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त खसरा नंबर 304 का दो नया खसरा नंबर 53, 54 रकबा कमशः 1.33, 0.52 आरे, खसरा नंबर 302, का दो नया खसरा नंबर 64, 65, 66 रकबा कमशः 0.14, 0.15, 0.17 आरे त्रुटि पूर्ण तरीके से शासकीय मद में दर्ज कर दिया गया है, आवेदित भूमि पर आवेदिका मकान, बाडी तथा कृषि कार्य करके काबिज कास्त है। अतः आवेदिका के द्वारा छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के तहत बंदोबस्त सुधार कर ग्राम अजिरमा स्थित भूमि नवीन खसरा नंबर 53, 54, 64, 65 व 66 के राजस्व अभिलेखो में अपना नाम दर्ज कराने का निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30/03/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 16/03/ 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न.

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पिता रमेश यादव जाति अहीर निवासी ग्राम सिरसी प.ह.न. रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र / पुत्री अभिषेक कुमार यादव का जन्म. दिनांक 10/01/2004 को ग्राम सिरसी में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र/पुत्री अभिषेक कुमार यादव का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सिरसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 20/03/2026 आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 14/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
ग्राम -केवरा प.ह.न. 12

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक झेलसाय पिता ननकू जाति पण्डो निवासी ग्राम केवरा प.ह.न. रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र /पुत्री स्व.ननकू आ.कल्लू का जन्म/मृत्यु दिनांक 13/11/2010 को ग्राम केवरा में हुई है, अज्ञानतावश जन्म/मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र/पुत्री स्व.ननकू आ.कल्लू जन्म/मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत केवरा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 18/03/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 02/03/2026को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील
भैयाथान जिला सूरजपुर (छःग)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न. 1

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामधनी सिह पिता लाल साय सिंह जाति गोड निवासी ग्राम बैजनाथपुर (ल)प.ह.न 01 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश का दिया गया है कि आवेदक के दादी स्व.दादी पवारो का मृत्यु दिनांक 15-11-1993 को ग्राम बैजनाथपुर (ल) में हुई है। अज्ञानतावश मृत्य पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने दादी पवारो.का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत बैजनाथपुर (ल) को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 18/03/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 02/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार तहसील
भैयाथान जिला सूरजपुर (छःग)

जिगना मिजार्पुर पंचायत सहायकों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

जिगना। मिजार्पुर के छानबे ब्लॉक मुख्यालय पर सोमवार को पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन छानबे के बैनर तले पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष सुबेदार यादव तथा उपाध्यक्ष इंदू मौर्या के नेतृत्व में पंचायत सहायकों का प्रतिनिधिमंडल ब्लॉक मुख्यालय पहुंचा और खंड विकास अधिकारी रामपाल को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए उस पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। पंचायत सहायकों ने कहा कि वे ग्राम पंचायतों में डिजिटल कार्यों से लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने मांगों के समाधान की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे पंचायत स्तर पर कार्य व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद खंड विकास अधिकारी छानबे रामपाल ने पंचायत सहायकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को संबंधित स्तर पर भेजकर उचित कार्रवाई के लिए प्रयास किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष आलोक शुक्ला, सचिव करफूलाल, टेक्निकल टीम के वरिष्ठ सदस्य अजयकांत शुक्ला, अनिल बिंद (जिला मीडिया प्रभारी), महामंत्री विंध्यप्रकाश जायसवाल, उपसचिव अर्चना देवी, मीडिया प्रभारी सीमा गौतम सहित छानबे ब्लॉक के सभी पंचायत सहायकों की उपस्थिति सराहनीय रही। पंचायत सहायक यूनियन छानबे की प्रमुख मांगें पंचायत सहायकों ने अपने 13 सूत्रीय मांग पत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया है। इनमें विभाग द्वारा पंचायत सहायकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने, समय से मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने तथा पंचायत सचिवालय में स्टेशनरी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा सचिवालय पर इंटरनेट, वाई-फाई और सिम कार्ड रिचार्ज की व्यवस्था, महिला पंचायत सहायकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने, स्वच्छ पेयजल और वाशरूम की सुविधा उपलब्ध कराने तथा महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने की मांग भी शामिल है। यूनियन ने ओएसआर खाता संचालन में पंचायत सहायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने, समय-समय पर प्रशिक्षण में बुलाए जाने पर यात्रा भत्ता देने, बीएलएस रिचार्ज प्लस सर्विस चार्ज की व्यवस्था करने और सभी पंचायत सहायकों को डिजिटल कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता का स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। इसके साथ ही विकास खंड और जनपद स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शासन द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने तथा रसौली, बौडई, भिलगौर और डंगहर ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायकों का लंबित मानदेय जल्द से जल्द दिलाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। पंचायत सहायकों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।

मातृ वंदन योजना में छत्तीसगढ़ ने ऐसे ही नहीं मारी बाजी : शिकायतों का तेज निराकरण और मंजूरी पर फोकस कर हासिल किया देश में पहला स्थान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना को लाभार्थियों तक पहुंचाने में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा है। इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार न सिर्फ जनकल्याणकारी योजनाओं को तेजी से अमल में लाती है, बल्कि प्रशासनिक सक्रियता से उसे हर तबके तक समय पर पहुंचाने के अपने वादे को पूरा करती है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करने की इस केंद्रीय योजना के तेजी से क्रियान्वयन और शिकायतों का त्वरित निपटान कर छत्तीसगढ़ ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह सिर्फ एक सरकारी योजना का राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे आंगनबाड़ी कार्यकताओं से लेकर पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी और राज्य स्तर के अधिकारियों तक के सेवा, समर्पण और दृढ़ निश्चय से हासिल की गई उपलब्धि है। जच्चा एवं बच्चा का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान इस दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

ऐसे मिली उपलब्धि

प्रशासनिक अमले द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लगातार मॉनिटरिंग की गई और लाभार्थियों के पंजीयन पर मुख्य रूप से फोकस किया गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए वर्ष 2023-24 में जहां 1,75,797 गर्भवती महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन

करवाया था, वहीं वर्ष 2024-25 में 2,19,012 रजिस्ट्रेशन किए गए। इसे ही लक्ष्य मानते हुए वर्ष 2025-26 में फरवरी तक 2,04,138 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया जो लक्ष्य का 93.3 प्रतिशत है। रजिस्ट्रेशन के बाद इसे तुरंत मंजूरी देने पर फोकस किया गया। तय प्रक्रिया के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकताओं द्वारा फार्म भरने, पर्यवेक्षक द्वारा इसके सत्यापन और परियोजना अधिकारी और राज्य स्तर पर मंजूरी देने में तेजी लाई गई। भरे गए आवेदनों के 83 प्रतिशत का परीक्षण कर इसे भुगतान के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिली स्वीकृति की दर भी सबसे ज्यादा 83.87 रही है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी शिकायतों के निराकरण के संबंध में आंकड़ों का परीक्षण किया गया। लाभार्थियों की ज्यादातर शिकायतें भुगतान न होने को लेकर थी। इस पर तत्काल ध्यान दिया गया और कोई कमी थी तो उसे दूर किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार के आंकड़ों में 30 दिन से ज्यादा लंबित शिकायतों की संख्या 7 प्रतिशत पाई गई है। इसके बावजूद 93 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर राज्य पहले स्थान पर रहा। यदि तीन वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कुल 5,98,947 गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें से 5,40,624 को स्वीकृति दे दी गई। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और उससे पूर्व पौष्टिक आहार व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार इस योजना के तहत 5 हजार रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर एकमुश्त 6 हजार रुपये देती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के समय 1,000 रुपये, 6 माह बाद 2,000 रुपये और बच्चे के जन्म, पंजीकरण और टीकाकरण के बाद 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसका मकसद संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और शिशु मृत्यु दर को कम करना है।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश: मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने शिविर में स्वयं स्वास्थ्य जांच कराकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का सशक्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवनशैली में शारीरिक गतिविधियों में कमी आने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत

आवश्यक हो गई है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने से व्यक्ति समय रहते जागरूक रहकर आवश्यक सावधानी अपनाते हुए गंभीर बीमारियों से बचाव कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध राज्य की नींव होते हैं। मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर न केवल लोगों को जागरूक करते हैं, बल्कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, संचालक स्वास्थ्य संजीव कुमार झा, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक रितेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कोण्डागांव जिले का मांदरी नृत्य दल भारत ट्राइब फेस्ट-2026 में करेगा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कोण्डागांव जिले का लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। यह दल नई दिल्ली में आयोजित भारत ट्राइब फेस्ट-2026 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। उल्लेखनीय है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में इस दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस उपलब्धि के लिए देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों दल को सम्मानित भी किया गया था। कलेक्टर कोंडागांव श्रीमती पन्ना ने जिले के मांदरी नृत्य दल के कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कोण्डागांव जिले के लिए गर्व का विषय है कि यहां के लोक कलाकारों का दल राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कलाकार अपनी प्रस्तुति से बस्तर की समृद्ध लोक संस्कृति को देशभर में पहचान दिलाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और कोण्डागांव जिले का नाम रोशन करेंगे। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि भारत ट्राइब फेस्ट का आयोजन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र प्रयागराज द्वारा 18 मार्च से 21 मार्च 2026 तक सुंदर नर्सरी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा

अबूझमाड़ की बेटी वनिता नेताम ने ह्यआदि पर्व 2026 में रचा इतिहास : वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। नवा रायपुर स्थित आदिवासी संग्रहालय में 13 एवं 14 मार्च 2026 को आयोजित ह्यआदि पर्व 2026 में छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की भव्य झलक देखने को मिली। इस आयोजन में प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के प्रतिभागियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक परंपराओं की आकर्षक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र से शामिल हुई प्रतिभागी वनिता नेताम ने पारंपरिक जनजातीय वेशभूषा में मंच पर अपनी संस्कृति की शानदार प्रस्तुति दी। उनकी पारंपरिक पोशाक और आभूषणों ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण पैदा किया और उपस्थित दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित ट्राइबल अटायर शो को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्र्स में दर्ज किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में भाग लेकर वनिता नेताम ने भी अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, जो नारायणपुर जिले और अबूझमाड़ क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। आदि पर्व 2026 का आयोजन आदिवासी संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित करने तथा उसे देश-दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। इस मंच के माध्यम से जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को व्यापक पहचान मिल रही है।

छत्तीसगढ़ के पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल, देशभर के टूर ऑपरेटरों ने देखी छत्तीसगढ़ की अनोखी झलक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार और राज्य की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को देश-दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित फेम ट्रिप के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों से आए टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंट्स ने बस्तर, मैनपाट और जशपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखा और उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। फेम ट्रिप के दौरान प्रतिनिधियों को बस्तर जिले के विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया साथ ही बोटिंग भी कराई गई, जिसने उनके अनुभव को और रोमांचक बना दिया। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने चित्रकोट स्थित प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन भी किए। बस्तर की जीवंत लोक संस्कृति से परिचित कराने के लिए प्रतिनिधियों को यहां के प्रसिद्ध हाट-बाजार भी ले जाया गया, जहां उन्होंने पारंपरिक मुर्गा लड़ाई जैसे स्थानीय सांस्कृतिक आयोजनों को देखा और बस्तर की विशिष्ट जनजातीय परंपराओं को समझा। इस भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों को ऐतिहासिक नगरी बारसूर भी ले जाया गया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध बत्तीसा मंदिर और भगवान गणेश की अद्भुत एवं प्राचीन मूर्तियों का अवलोकन किया। इन ऐतिहासिक धरोहरों ने प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया। फेम ट्रिप के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बस्तर के कमिश्नर, आईजी और एसपी से भेंट कर क्षेत्र में पर्यटन विकास, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन सुविधाओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त

किया कि बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रतिनिधियों को मैनपाट के खूबसूरत पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया गया। यहां उन्होंने करमा एथेनिक रिजॉर्ट और सैला रिसोर्ट का दौरा किया तथा मैनपाट की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का अनुभव किया। इसके अलावा प्रतिनिधियों को कुनकुरी स्थित गिरजाघर, जशपुर का राजपुरी जलप्रपात तथा केरे विलेज जशपुर में स्थित महुआ होमस्टे जैसे आकर्षक पर्यटन स्थलों से भी परिचित कराया गया। इन स्थलों ने छत्तीसगढ़ के इको-टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को उजागर किया। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित यह फेम ट्रिप 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 28 टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट्स शामिल हैं। इन प्रतिनिधियों को दो समूहों में विभाजित कर राज्य के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार और पर्यटन बोर्ड का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के टूर ऑपरेटरों को राज्य की पर्यटन संभावनाओं से सीधे परिचित कराना है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार कर सकें। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड राज्य के पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा तथा प्रबंध संचालक विवेक आचार्य के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। इस फेम ट्रिप से जुड़े प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और यहां के लोगों के आत्मीय आतिथ्य की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और वे अपने-अपने राज्यों में छत्तीसगढ़ को एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देंगे। फेम ट्रिप का समापन 18 मार्च को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के साथ होगा, जहां दोनों समूहों के प्रतिनिधि एकत्रित होंगे और छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की ओर से राज्य की पर्यटन संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। इस पहल से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिले में लिखी जा रही है विकास की नई गाथा

पीएमजीएसवाई अंतर्गत 126 करोड़ की लागत से 42 सड़कों का होगा निर्माण, निविदा प्रक्रिया जारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और विकासोन्मुखी सोच के अनुरूप जशपुर जिले में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जिले में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार ठोस पहल की जा रही है इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में जिला विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीते दो वर्षों से अधिक के कार्यकाल में आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से धरातल पर दिखाई देने लगा है। जिले के गांवों से लेकर शहरों तक सड़कों, पुलों और पुलियों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे आवागमन सुविधाजनक और सुरक्षित बन रहा है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 42 नई सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों का निर्माण 126 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। वर्तमान में सभी सड़कों की निविदा प्रक्रिया जारी कर दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। स्वीकृत सड़कों में जशपुर विकासखंड में 5 सड़कें, मनोरा विकासखंड में 7 सड़कें, दुलदुला विकासखंड में 7 सड़कें, कुनकुरी विकासखंड में 13 सड़कें तथा फरसाबहार विकासखंड में 10 सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सड़कों और पुल-पुलिया के निर्माण से बदल रही है जिले की तस्वीर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निदेर्शानुसार जिले में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देते हुए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विकास की रोशनी पहुँच रही है। लगातार सड़कों, पुलों और पुलियाओं को मिल रही स्वीकृति तथा उनके निर्माण से न केवल आवागमन सुगम हो रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था

को भी मजबूती मिल रही है। बेहतर सड़क संपर्क के कारण कृषि उत्पादों का परिवहन आसान हो रहा है, जिससे किसानों को अपने उत्पाद समय पर बाजार तक पहुँचाने में सुविधा मिल रही है। साथ ही निर्माण कार्यों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों तक पहुँचना अधिक सरल हो रहा है। बेहतर संपर्क मार्गों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक भी लोगों की पहुँच आसान हो रही है और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को शीघ्र अस्पताल पहुँचाने में मदद मिल रही है। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रहे विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों को भी इन सड़कों से विशेष लाभ मिल रहा है। सड़कों के निर्माण से इन समुदायों का संपर्क विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, मंडियों तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं से सुदृढ़ हो रहा है। इससे उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

जिले में सड़कों के व्यापक विस्तार से न केवल आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित हुआ है, बल्कि इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। इन विकास कार्यों के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है और इसका सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग और बलिदान देश की अमूल्य धरोहर: मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को 23 मार्च को बेमेतरा जिले में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री साय ने आमंत्रण के लिए संस्था के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान देश के इतिहास में अमूल्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। यह केवल कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति, समर्पण और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देने का भी सशक्त माध्यम है।

जनगणना के लिए हुआ जिला स्तरीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाली जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य राज्य में 1 मई से 30 मई तक किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में रविवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण में ट्रेनर द्वारा जनगणना की रूपरेखा, कानूनी प्रावधान, डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा डेटा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस दौरान जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता, संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सड़क दुर्घटना पीड़ितो को पीएम राहत से मिलेगा डेढ़ लाख का नि:शुल्क उपचार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में भी अब शासन की महत्वपूर्ण योजना सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार की सुविधा प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिले की मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. कपिल देव पैंकरा के निर्देशन में संपन्न हुआ। के संबंध में रायपुर से ऑनलाइन वी.सी के माध्यम से योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि पीएम - भारत योजना उपचार राज्य के मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी अस्पतालों में किया जा सकेगा तथा लाभार्थी अथवा उसके परिजनों से किसी प्रकार की राशि नहीं पंजीयन तथा संचालन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अस्पतालों द्वारा दुर्घटना पीड़ित का त्वरित पंजीयन पोर्टल पर किया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेज एवं उपचार विवरण समय पर अपलोड किए जाएंगे।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जिले के समस्त शासकीय पंजीकृत अस्पतालों के लिए एक दिवसीय समीक्षा बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया। इसके साथ ही 16 मार्च को योजना के संबंध शासकीय एवं निजी पंजीकृत अस्पतालों में योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर के दौरान त्वरित उपचार तथा अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अधिकतम 07 दिवस तक अथवा 1.50 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति का ली जाएगी। कार्यशाला के दौरान राज्य से डीआरएम, तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थित में जिला से जिला नोडल एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित रहे सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को योजना के प्रमुख प्रावधानों, उपचार प्रक्रिया, क्लेम सबमिशन, डीएआरआईटी पोर्टल में बैठक में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिले के समस्त शासकीय एवं निजी अस्पतालों में 24×7 आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिले के सभी अस्पतालों को ई-डीएआर पोर्टल में पंजीयन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

कुदरगढ़ महोत्सव के तैयारियो की कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जानकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। आगामी 23 से 25 मार्च तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव-2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित जिला अधिकारी वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए। बैठक में महोत्सव की अद्यतन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही 23 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित आगमन को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। लोक निर्माण विभाग के अभियंता से कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, स्टॉल व्यवस्था तथा पार्किंग प्रबंधन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पेयजल व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभी से पर्याप्त टैंकर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस वर्चुअल बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

10वीं ओपन हिन्दी परीक्षा में 5 एवं 12वीं में 1 नकलची धराया

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। 10 वीं एवं 12वीं ओपन की परीक्षा के पहले दिन 6 नकलची पकड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। परीक्षाओं के संचालन के लिए जिले में

जिले में 9 परीक्षा केन्द्र बनाये गए है। 12वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या-1086 में से 992 परिक्षार्थी उपस्थित रहे जबकि 94 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं 10वीं दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या-804 में से 752 परिक्षार्थी उपस्थित एवं 52 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहले दिन मंगलवार को दोनों कक्षाओं के लिए हिंदी विषय की परीक्षाएं आयोजित थी। जिले में गठित उड़नदस्ता दल प्रभारी अधिकारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान एवं टीम के द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें 1 नकल प्रकरण दर्ज किया गया है इसी प्रकार उड़नदस्ता दल प्रभारी अधिकारी तहसीलदार ओड़गी एवं टीम के निरिक्षण में 10वीं में 05 नकल प्रकरण दर्ज किया गया है।

जिले के अस्पतालों में किया गया अग्नि सुरक्षा का पूर्वाभ्यास कर्मचारी हुए जागरूक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन में गर्मी के मौसम में अग्नि दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए जिला सूरजपुर के स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करसी एवं एस.आर.पी.आर. हॉस्पिटल सूरजपुर में अग्नि सुरक्षा उपकरणों के संचालन का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। इस पूर्वाभ्यास के दौरान संबंधित विशेषज्ञों द्वारा अग्निशमन उपकरणों की प्रचलन विधि को

विस्तार से समझाया गया तथा आग लगने की स्थिति में की जाने वाली त्वरित कार्रवाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। तीनों स्वास्थ्य संस्थानों में उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने इस डेमो में सक्रिय रूप से भाग लिया और अग्नि सुरक्षा के प्रतिजागरूकता हासिल की। उल्लेखनीय है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील इमारतों में मरीजों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। ऐसे में गर्मी के मौसम से पूर्व इस प्रकार का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में अस्पताल का प्रत्येक कर्मचारी आग को नियंत्रित करने में सक्षम हो और किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

2 मवेशी तस्कर धराए 1.50 लाख के मवेशी जप्त, चंदौरा पुलिस की कार्रवाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले की चंदौरा पुलिस ने 2 मवेशी तस्करो से 1.50 लाख कीमत के मवेशी जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार बीते सोमवार को चंदौरा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि मवेशी तस्कर पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 24 एटी 5022 में अवैध रूप से

किया है। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने अवैध कार्यों पर पूर्णत: अंकुश लगाने और ऐसे कृत्य में शामिल लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए है। इसी तारतम्य में क्रूरतापूर्वक मवेशी भरकर अम्बिकापुर से उत्तरप्रदेश की ओर जा रहे है। सूचना पर पुलिस द्वारा चंदौरा चौक में नाकाबंदी लगाकर उक्त वाहन के आने पर उसे रोकवाया। वाहन में 2 व्यक्ति भूप सिंह फिरोजपुर थाना बिसौली जिला बदायूं उत्तरप्रदेश एवं वसीम खैरी थाना बिल्सी जिला बदायूं उत्तरप्रदेश मिले। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 4 नग जीवित व 1 नग मृत भैंसा पाया गया। दोनों व्यक्ति से मवेशी बिक्री व परिवहन संबंधी दस्तावेज की मांग किए जाने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। मामले में पिकअप वाहन एवं मवेशी जप्त कर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(घ) एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 के तहत कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी चंदौरा लक्ष्मण सिंह धुर्वे, एएसआई नीलकुसुम बेक व टीम सक्रिय रही।

प्रथम पुण्यतिथि पर याद किये गए छोटे राजा विन्ध्येश्वरी प्रताप सिंह

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

भैयाथान। झिलमिली स्टेट के छोटे राजा के नाम से विख्यात स्व. विन्ध्येश्वरी प्रताप सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर परिवारजन एवं क्षेत्रवासियों द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वार्षिक श्राद्ध पूजन के साथ ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया तथा सुंदरकांड पाठ भी संपन्न हुआ। इंद्रप्रस्थ भैयागढ़ी में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिजन एवं आमजन उपस्थित होकर स्व. श्री सिंह को याद किया। इस दौरान उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करते हुए रामेश्वर प्रताप सिंह ने कहा कि वे हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे तथा गांव के आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में दक्ष थे। यही कारण

था कि उस समय थाने में कम ही मामले पहुंचते थे और ग्रामीणों का उन पर गहरा विश्वास था। उन्होंने खेलों के प्रति उनके विशेष लगाव का उल्लेख करते हुए बताया कि वे फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी थे। जिला पंचायत सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि स्व. श्री सिंह ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखा, जिसका परिणाम है कि आज भी परिवार एकजुट है। उन्होंने बताया कि नवरात्र के दौरान कुदरगढ़ में उनकी पूजा-अर्चना की परंपरा आज भी परिवार द्वारा निभाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में आयोजित धार्मिक आयोजनों में वे काफी सक्रिय रहते थे। परिवारजन आज भी उनके बताए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में ललित सिंह, अमरेश्वर प्रताप सिंह, शिवम सिंह, योगेश प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह, आशीष सिंह सहित परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर

जिला: बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

eprocurement Portal : https//eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

निविदा सूचना क्रमांक : 07/व.ले.लि./2025-26 दिनांक 13.03.2026 निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 06.04.2026 (17.30 बजे) तक ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	सिस्टम निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत
1	187089	ढुढ़ीचुआ जलाशय योजना के यूनिट-1 हेड वर्क पर आर0डी0 210 मी. से 300 मी. के बीच नाला क्लोसर में बंड में मिट्टी कार्य, पउल फिलिंग बोल्डर टी पिचिंग एवं स्पील चैनल में आर0डी0 240 मी. पर शूटफॉल का निर्माण कार्य, आर0डी0 300 मी. से 495 मी. के बीच शेष मिट्टी का कार्य।	रू. 682.39 लाख।
2	187090	दातराम जलाशय योजना के यूनिट-1 शीर्ष कार्य के सेन्ट्रल स्टील संरचना के उप स्ट्रिम एवं डाउल स्ट्रिम के कटऑफ एवं फलोर का निर्माण कार्य एवं यूनिट-2 नहर में 05 नग व्ही0आर0बी0, 08 नग सी0डी0, 06 नग आऊटलेट संलचना और मुख्य नहर में मिट्टी का कार्य।	रू. 170.39 लाख।

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 20.03.2026 समय 17.30 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोट : निविदा मे भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/ पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियन्ता

जल संसाधन संभाग बलरामपुर

जिला: बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

कृते- मुख्य अभियन्ता

हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग

अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी-252607206/2

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिली आर्थिक सहायता

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। मातृत्व का समय किसी भी महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है। इस दौरान उचित पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और आर्थिक सहयोग माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है। ऐसे समय में शासन की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा बनी है। इस योजना का लाभ लेकर कई माताएं सुरक्षित मातृत्व का अनुभव कर रही हैं। इसी कड़ी में विकासखंड राजपुर के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र कोडाकुपारा निवासी श्रीमती शशी को भी इस योजना मातृत्व के दौरान सहारा बनकर आई। सीमित आय वाले परिवार से आने वाली श्रीमती शशी के लिए गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखना आसान नहीं था। मजदूरी पर निर्भर रहने के कारण आय का नियमित स्रोत भी नहीं था, जिससे गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त खर्च की चिंता बनी रहती थी।

जिला अस्पताल में हुआ शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ, 21 तक चलेगा अभियान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंगलवार को यहां जिला चिकित्सालय में शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ प्रारम्भ हुआ यह अभियान 17 मार्च से 21 अप्रैल तक पूरे जिले में संचालित रहेगा। उद्घाटन अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथियों ने माताओं को संबोधित करते हुए शिशु के शुरुआती वर्षों में उचित पोषण और नियमित टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया।अभियान में मिलेंगी ये सेवाएं इस अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को रतौंधी और अन्य बीमारियों से बचाव हेतु विटामिन ए की सिरप पिलाई जाएगी। साथ ही शिशुओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड सप्लीमेंट का वितरण किया

जाएगा। अभियान के दौरान उन बच्चों की विशेष रूप से पहचान की जाएगी जो किन्हीं कारणों से नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, ताकि उन्हें समय पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा बच्चों का वजन और ऊंचाई मापकर गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी और जरूरतमंद बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। माताओं को स्तनपान, पूरक आहार और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष परामर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण और पोषण सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि जिले का एक भी बच्चा इस सुरक्षा चक्र से वंचित न रहे।

अभिभावकों से अपील

स्वास्थ्य विभाग ने जिले के समस्त अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र ले जाकर इस अभियान का लाभ अवश्य उठाएं और अपने बच्चों के स्वस्थ व सुरक्षित भविष्य की नींव रखें।

एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, उपभोक्ता अफवाहों से बचें

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में राज्य में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

खाद्य विभाग के अनुसार राज्य में ऑयल कंपनियों के पास एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा इनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित न हों और अनावश्यक रूप से एलपीजी बुकिंग या पेट्रोल-डीजल का संग्रहण न करें। एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल के अवैध संग्रहण व दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध स्थलों पर जांच व कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं को एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे खाद्य विभाग के कॉल सेंटर 1800-233-3663 या 1967 तथा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0771-2511975 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में एलपीजी गैस की उपलब्धता, बुकिंग, वितरण एवं भंडारण को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे रिफिल सिलेंडर की बुकिंग निर्धारित अंतराल के बाद ही कराएं। ऑयल कंपनियों द्वारा दो बुकिंग के बीच शहरी क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। साथ ही किसी भी अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होकर बार-बार ऑनलाइन बुकिंग करने से बचने की अपील की गई है।

व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान स्थिति में गैस की आपूर्ति अत्यावश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। साथ ही बिना विस्फोटक लाइसेंस के अधिकतम 100 किलोग्राम तक ही एलपीजी भंडारण का प्रावधान है। इससे अधिक की आवश्यकता होने पर विधिवत मैनिफोल्ड सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य है।

जिला प्रशासन एवं ऑयल कंपनियों द्वारा एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी गैस एजेंसियों को अपने पास उपलब्ध एलपीजी स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित करने तथा प्रतिदिन जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आपातकालीन संपर्क

एलपीजी बुकिंग, वितरण या अन्य किसी समस्या के लिए उपभोक्ता अपने अधिकृत गैस वितरक, जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 92945-21998 या राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0771-2511975 तथा खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन अम्बिकापुर 18 मार्च 2026 8

सरगुजा फ्रंटलाइन

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो दिन फिल्ड विजिट अवश्य करें

कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक संपन्न

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अगले टीएल बैठक तक सभी विभाग सीएम जनदर्शन एवं पीजी पोर्टल को शून्य पर लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, वे पीजीएन पर फोकस करें।

कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी सतत फिल्ड विजिट कर कार्यों में गति लाएं। सप्ताह में कम से कम 2 दिन अवश्य रूप ने सभी विभाग स्थल निरीक्षण कर विभागीय कार्यों की वास्तविक स्थिति एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन करें। उन्होंने कहा कि फिल्ड विजिट आमजनों की समस्याओं को समझने का अच्छा माध्यम है, इसलिए लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं के यथाशीघ्र निराकरण की कार्रवाई हो। उन्होंने विशेषकर राजस्व,

पंचायत, लोक निर्माण, वन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी विकास विभाग सहित सभी निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को फिल्ड में अनिवार्य रूप से जाने कहा। बैठक में छात्रावासों के निरीक्षण, दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण, धान उठाव, डीएमएफ अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति, स्थल निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों में कार्रवाई के सम्बन्ध में विभागों से जानकारी ली। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, अपर कलेक्टर राम सिंह ठाकुर, नगर निगम कमिश्नर डीएन कश्यप, सभी एसडीएम एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अटैच शिक्षकों को विद्यालयों में वापस भेजें

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आश्रम, छात्रावासों में अटैच शिक्षकों को विद्यालयों में वापस भेजें, ध्यान रहे कोई भी विद्यालय अटैचमेंट के कारण एकल या द्वि-शिक्षकीय ना रहे। उन्होंने कहा कि यदि विद्यालय में अतिशेष शिक्षक हों, तभी अटैच किया जाए। उन्होंने विद्यालयों में अनुपस्थित शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई पर जानकारी ली और कहा कि संबंधित पर विभागीय जांच अवश्य करवाएं। बैठक में कलेक्टर ने अपार आईडी निर्माण में प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से जन्म प्रमाणपत्र निर्माण की जानकारी ली और कहा कि जिनका प्रमाण पत्र बनकर तैयार है, उन्हें पंचायत सचिवों के माध्यम से जारी करवाएं। इसके पश्चात शिक्षा विभाग आधार कार्ड बनवाने आवश्यक कार्रवाई करे। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र निर्माण की अनुभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, इस हेतु ग्राम सभा आयोजित करवाया जाए।

पीवीटीजी समुदायों के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश दिलाएं

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देश दिए कि आश्रम-छात्रावासों में रहने वाले ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराएं, जो इस वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा दे रहे हों। उन्होंने कहा ध्यान रहे कि ये सभी बच्चे आगामी कक्षा छठवीं एवं नवमीं में अवश्य प्रवेश लें। स्वयं मॉनिटरिंग करें और शाला त्याग की मंशा वाले बच्चों के अभिभावकों से मिलकर उन्हें प्रेरित करें। पीवीटीजी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा सशक्त माध्यम है, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सरगुजा ओलम्पिक के संभागस्तरीय आयोजन पर चर्चा

बैठक में कलेक्टर ने आगामी 21 से 23 मार्च तक जिले में आयोजित होने वाले सरगुजा ओलम्पिक के संभागस्तरीय आयोजन की आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आयोजन के शुभारंभ अवसर पर 21 मार्च को मुख्यमंत्री का आगमन प्रस्तावित है। आयोजन की गरिमा को ध्यान में रखकर समय सीमा में तैयारियां सुनिश्चित करें। वे खिलाड़ियों की आवासीय व्यवस्था की जानकारी लिए और कहा कि सभी स्थानों पर विद्युत, पेयजल की आपूर्ति रहे, सुरक्षा की दृष्टि से होम गार्ड की ड्यूटी लगाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रहे, स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव रहे। उन्होंने भोजन व्यवस्था की जानकारी ली और कहा कि पूरे आयोजन में अव्यवस्था को स्थिति ना बने। उन्होंने खेल मैदानों की भी जानकारी ली और कहा कि प्रतियोगिता के रेफरी को निर्देशित करें कि सभी प्रतियोगिता अच्छे से संचालित हो। कलेक्टर ने बैठक के पश्चात राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम अंतर्गत एक वर्ष एवं तहसीलदार अंतर्गत 6 माह के प्रकरण लंबित ना रहे। राजस्व मामले को लेकर आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो।

भाजपा अजजा मोर्चा के साथ ग्रामीणों ने पुश्तैनी भूमि को बचाने कलेक्टर से लगाई गुहार

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी अधिकारों के सुरक्षा और कार्रवाई की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। भाजपा सरगुजा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नरकालो और चोड़ेया के आदिवासी समाज के ग्रामीणों ने कलेक्टर सरगुजा को शिकायत पत्र सौंपा है और भोले-भाले आदिवासियों की पुश्तैनी भूमि पर बाहरी विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है।

ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा सरगुजा अजजा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बिंदेश्वरी लाल पैकरा ने कहा कि नरकालो व चोड़ेया के विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो कई पीढ़ियों से अपनी पुश्तैनी भूमि पर निवास करते आ रहे हैं। उनका जीवनयापन, संस्कृति, परंपरा एवं धार्मिक आस्था पूरी तरह जल, जंगल और जमीन पर निर्भर है। यह क्षेत्र भी पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, जहां आदिवासी भूमि की सुरक्षा हेतु विशेष संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान लागू है परंतु विगत कुछ वर्षों से नवादा बिहार एवं अन्य क्षेत्रों से आए हुए मुस्लिम समाज के व्यक्तियों द्वारा गांव के आदिवासी भूमि पर जबरन मकान निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया है और बिना किसी वैधानिक अधिकार के स्थायी बसावट की जा रही है। बिन्देश्वरी लाल पैकरा ने बताया कि नरकालो निवासी बदलू पिता प्रधान का राजाकोट में लगभग एक एकड़ भूमि है, जिसे कुरैशा और हुसैन ने कब्जा करके रखा है। इसी प्रकार गिरीश पिता घुरऊ की लगभग 87 डिसमिल भूमि को नसरुद्दीन, नरकालो निवासी बसंती पति शिव कंवर की 1.5 एकड़ भूमि को जलालुद्दीन एवं नसरुद्दीन, नरकालो निवासी घूरऊ पिता दशरथ कंवर की 1.5 एकड़ भूमि को मोहमुद्दीन, ग्राम चोड़ेया निवासी शांति पिता अमरूष मझवार की लगभग 3 एकड़ भूमि को फिरदौस तथा चोड़ेया निवासी जेठू पिता काशी बारगाह की लगभग 4 एकड़ भूमि को हुसैन द्वारा बलात कब्जा कर लिया गया है ।

भाजपा सरगुजा अजजा मोर्चा के महामंत्री रविकांत उरांव ने बताया कि जब गांव के आदिवासी समाज के लोगों द्वारा इस कृत्य का विरोध किया जाता है तो इन्हें डराया धमकाया जाता है, मारपीट की धमकी दी जाती है। अशिक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा लगातार हमारे समाज का शोषण किया जा रहा है। आगे रविकांत उरांव ने कहा कि इन अवैध कब्जों से आदिवासियों की कृषि भूमि कम होती जा रही है, आजीविका प्रभावित हो रही है। हमारी पारंपरिक संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा गांव की जनसंख्या संरचना भी बदल रही है, जिससे भविष्य में हमारे अस्तित्व और अधिकारों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। भाजपा सरगुजा अजाजा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ पहुंचे पीड़ित ग्रामीणों ने अवैध कब्ज़े को तत्काल हटाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर भाजपा अजजा मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉ. शिवमंगल सिंह, राजेंद्र पैकरा, तेजबल राम नागेश, जितेंद्र कुजूर, सुनील कुमार, संजय सिंह, अर्जुन मुंडा, कृष्ण कोरवा, अवधेश केरकेट्टा, उमेश किष्पोट्टा, बदलु, गिरीश, लक्ष्मण, बसन्ती, तुलासो, शांति, मंजली और जहगन राम सहित आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे ।

गिरकर अचेत हुई महिला की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। वृद्ध महिला घर से कुछ फासले पर गिरकर अचेत हो गई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिला के प्रेमनगर थाना अंतर्गत ग्राम नमना की बिद्रा बाई पति स्व. अमर लाल 60 वर्ष, 16 मार्च की शाम को घर के परछी में खाना बना रही थी। मौके पर वृद्धा का पुत्र मदन, पुत्रवधु काजल, पोता-पोती भी मौजूद थे। इसी बीच बिद्रा बाई अपने पुत्र मदन को बाहर जा रही हूं, सब्जी देखना कहते हुए घर से बाहर निकली, और कुछ ही फासले पर गिर गई। वृद्धा की चीख-पुकार सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे, लेकिन वह बात नहीं कर रही थी। स्वजन निजी वाहन से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान 17 मार्च को देर रात दो बजे महिला की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

स्वीकृत सेटअप अनुसार रिक्त पदों पर हो भर्ती, फिर करें संलग्नीकरण समाप्त

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष ने कहा-स्वास्थ्य सेवाएं होंगी प्रभावित

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शासन ने सरगुजा संभाग के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि संभाग में संलग्न समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से संलग्नीकरण समाप्त कर मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किया जाए और पदस्थापना स्थल में उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं को प्रमाण पत्र प्रेषित करें।

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने आदेश के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं का ध्यानाकर्षण कराया है कि सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य संस्थाओं में शासन से स्वीकृत कुल पदों में लगभग 35 से 40 प्रतिशत पद (चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी) रिक्त है। संभाग के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य प्रभावित न हो इसलिए ज्यादातर संलग्नीकरण कार्य जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर एवं आवश्यकता अनुसार किया गया है। समस्त संलग्नीकरण समाप्त किए जाने से स्वास्थ्य संबंधित कार्य प्रभावित होंगे, जिसके कारण आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में परेशानी होगी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में शासन से स्वीकृत सेटअप अनुसार 35 से 40 प्रतिशत रिक्त पद पर जब तक भर्ती नहीं हो जाता तब तक आम जनता को बगैर संलग्नीकरण का पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, समस्त संलग्नीकरण समाप्त किए जाने से अगर किसी संस्थाओं में पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण आम जनता को परेशानी होती है या किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग एवं उच्च अधिकारियों की होगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे स्वास्थ्य संस्थाएं जहां स्वीकृत सेटअप अनुसार कर्मचारी कम हैं वहां से संलग्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हटाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी संस्थाओं से ही कर्मचारियों एवं अधिकरियों को हटाया जाए जहां आवश्यकता न हो या फिर स्वीकृत सेटअप से ज्यादा कर्मचारी एवं अधिकारी पदस्थ हों, या फिर संलग्न कर्मचारी एवं अधिकारी की मूल पदस्थापना पर कार्य प्रभावित हो रहा हो। कई स्वास्थ्य संस्थाओं में कर्मचारी कम होने के कारण कार्य की अधिकता के कारण कर्मचारी एवं अधिकारी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, ऐसे में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि जनहित में स्वास्थ्य संस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार किए गए संलग्नीकरण को समाप्त कर कार्यमुक्त नहीं किया जाए, या वर्तमान में कार्य कर रहे संस्थाओं के संस्था प्रमुखों से संलग्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपयोगिता, आवश्यकता की जानकारी लेकर ही कार्यमुक्त करने हेतु निर्देश जारी किए जाएं।

किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन, जर्जर भवन के मरम्मत की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन लखनपुर। सरगुजा जिले में आज भी कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी भवन के जर्जर होने तथा किराए के भवन में केंद्र का संचालन होने से कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं व बच्चों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला लखनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम अरगोती सड़क पारा का है।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण लगभग 7 वर्ष पूर्व लाखों रुपये व्यय करके आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराया गया था। नए आंगनबाड़ी भवन में लगभग एक वर्ष केंद्र का संचालन किया गया, और भवन का फर्स लगभग दो फीट नीचे धंस गया, जो बच्चों के बैठने योग्य नहीं था। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजती टोप्पो के द्वारा विगत कई वर्षों से किराए के मकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित ग्रामीणों ने भवन के मरम्मत की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक शासन-प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी भवन का मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

जहरीले पदार्थ का सेवन की महिला, इलाज दौरान मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शराब का सेवन करने के बाद जहरीले पदार्थ का महिला सेवन कर ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम गेलहाचुआं, बरगवां का आनन्द टोप्पो 11 मार्च को बैल चराने के लिए गया था। घर में उसकी पत्नी सोनामनी टोप्पो 43 वर्ष अकेले थी, जो दो-तीन दिन से लगातार शराब का सेवन कर रही थी। शाम को करीब 5 बजे मवेशियों को लेकर महिला का पति आनन्द घर लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने और खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बैल, बकरी को बांधकर जब वह दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला, और अंदर गया तो सोनामनी पलंग के नीचे पड़ी थी, और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सिर के पास एक गिलास रखा था, जिसमें स्याही के रंग का तरल पदार्थ था। पति आननफानन में निजी वाहन की व्यवस्था करके उसे अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचा, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे भर्ती कर लिया। 16 मार्च को महिला को रेफर करने पर शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां इलाज के बीच शाम करीब 3.50 बजे चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु आवेदन 20 तक

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए जिले के पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में राज्य के शासकीय विद्यालयों के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने कक्षा 7वीं न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 5 प्रतिशत की छूट) के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही आवेदक के माता-पिता या पालक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, अशासकीय विद्यालय एवं आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु सरगुजा जिले में कुल 07 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, कक्षा 7वीं उत्तीर्ण अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, यदि विद्यार्थी माता-पिता के स्थान पर किसी अन्य पर आश्रित है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।

शोध की निरंतरता को बाधित कर रहा विवि प्रशासन का सुस्त रवैया

कुलपति से पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने शोधार्थियों के भविष्य से जुड़े अत्यंत संवेदनशील विषय पर अपना पक्ष रखते हुए कुलपति को पत्र लिखकर सत्र 2026 में पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा को अनिवार्य रूप से आयोजित करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में विश्वविद्यालय की वर्तमान कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी बाधा और शोधार्थियों के साथ घोर अन्याय बताया है। रचित मिश्रा ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम बार 10 नवंबर 2023 को पी.एच.डी. प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे और 10 दिसंबर 2023 को इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। उस समय की पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक छवि को नई ऊंचाइयां दी थी। इसके पश्चात वर्ष 2026 का प्रथम त्रैमासिक समाप्त होने को है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोबारा इस परीक्षा की सुध लेना आवश्यक नहीं समझा। 2023 से 2026 के बीच तीन वर्षों का लंबा अंतराल न केवल शैक्षणिक कैलेंडर का उल्लंघन है, बल्कि उन हजारों प्रतिभावान छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ है, जो लंबे समय से शोध कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2026 में भी परीक्षा आयोजन

के संबंध में किसी भी प्रकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे प्रदेश के छात्र-छात्राओं के मध्य गहन अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति है। एक ओर जहां सरकार उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का सुस्त रवैया शोध की निरंतरता को बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि लंबी देरी का प्रतिकूल प्रभाव न केवल विद्यार्थियों के करियर और समय प्रबंधन पर पड़ रहा है, बल्कि निरंतर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भारी मानसिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सत्र 2026 में पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा का शीघ्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन सुनिश्चित किया जाए। पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को सचेत किया है कि यदि इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आजाद सेवा संघ छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक और वैधानिक माध्यमों से कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

Since 2003
Based on CBSE Syllabus
Admission Open
Nursery to 10th
Milestones School
English Medium
Add. : Behind Central Bank Gudri Chowk, Ambikapur Mob. 9826190902
Office Time : 10 AM to 2 PM

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर